

कष्ट सहने पर ही हमें अनुभव होता है और दर्द हो, तभी हम सीख पाते हैं।

RNI No :- DELHIN/2023/86499  
DCP Licensing Number :  
F.2 (P-2) Press/2023

वर्ष 02, अंक 348, नई दिल्ली। सोमवार, 24 फरवरी 2025, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

03 सी एम रेखा गुप्ता प्रथम धर्मतीर्थ प्रवर्तन में शामिल होंगी

06 अल्पावधि पाठ्यक्रमों में उज्ज्वल भविष्य का निर्माण करें

08 भारत ने पाकिस्तान से लिया 2017 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में हार का बदला

## दिल्ली परिवहन आयुक्त जनता के स्थान पर वाहन डीलरों के हितैषी फिर भी दिल्ली सरकार, मुख्य सचिव और उपराज्यपाल आखिर चुप क्यों?

दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा पंजीकृत नए वाहन एवं जारी हो रहे ई रिक्शा चालक लाइसेंस, जनता की सुरक्षा के खिलाफ।

संजय बाटला

नई दिल्ली। दिल्ली परिवहन विभाग वाहन पंजीकरण के प्रति अनिवार्य स्वयं द्वारा जारी स्टेट अप्रूवल को दरकिनार करके वाहन निर्माताओं और डीलरों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से वाहनों का कर रहे हैं पंजीकरण जिससे सड़कों पर दुर्घटनाओं के आसार सदैव बना रहेगा।

1. किसी भी वाहन को भारत की सड़कों पर चलने से पहले वाहन को वाहन जांच एजेंसी से जांच टेस्ट पास सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होता है और उसी जांच प्रमाण पत्र के आधार पर राज्य परिवहन विभाग उस वाहन को अपने राज्य में पंजीकरण की इजाजत के लिए स्टेट अप्रूवल प्रमाण पत्र जारी करते हैं और उसी के अनुसार पंजीकरण करने वाली शाखाएं वाहन पंजीकृत करते हैं लेकिन देखने में आया है की दिल्ली में वाहन डीलर जो वाहन पंजीकृत करवा रहे हैं और बेच रहे हैं वह वाहन जांच एजेंसी द्वारा उन्हें जारी प्रमाण पत्र और दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा जारी स्टेट अप्रूवल के अनुसार नहीं हैं पर फिर भी पंजीकृत हो कर सड़कों पर दौड़ रहे हैं।

2. देखने में आया है की दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा वाहन डीलरों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से दिल्ली में जनता के लिए उपलब्ध ऑनलाइन जॉइंटिंग/चाइस नंबर के लिए दो तरह का ऐप



बनाया हुआ है जिससे जनता को आनलाइन प्रक्रिया से नंबर प्राप्त करना संभव नहीं होता पर वही नंबर वाहन डीलर उपलब्ध करवा देता है और अपनी इच्छा से रकम वसूल रहे हैं, फिक्ता प्रनहित और जनप्रिय हैं ना परिवहन विभाग का फैसला ?

उद्देश्य से रिक्शा चालक को रिक्शा बेचने के लिए अनिवार्य रिक्शा चालक लाइसेंस उपलब्ध करवाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस को जारी करते समय जो नियम के तहत ट्रेनिंग सर्टिफिकेट अनिवार्य है उसे आनलाइन अपलोड करवाने की जगह मैनुअल रूप से ले रहे हैं जिसके कारण ड्राइवर के ट्रेनिंग

सर्टिफिकेट की सत्यता पर सवाल बनता है और जनता की सुरक्षा से खिड़वाड़ अब सवाल यह उठता है की परिवहन आयुक्त जनता की जगह डीलरों के हितैषी फिर भी दिल्ली सरकार, मुख्य सचिव और उपराज्यपाल है चुप। आखिर क्यों ?

**टोलवा ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)**

**TOLWA**

website : www.tolwa.in  
Email : tolwadelhi@gmail.com  
bathlasanjaybathla@gmail.com

रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम - डीएल - 0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण

रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए - 4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063  
कॉर्पोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मैन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ बड़ौदा दिल्ली 110042

## दिल्ली मेट्रो ने अपना ही पिछला रिकॉर्ड कर दिया ध्वस्त, बनाया ये कीर्तिमान

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। नई दिल्ली मेट्रो ने इतिहास रच दिया है। दिल्ली की लाइफ-लाइन राजधानी लाइनों लोगों को उनके मॉडल तक ले जाती है। हर रोज कोई ना कोई कीर्तिमान रचती है। अब अगर पूरे देश की मेट्रो की बात करें तो दिल्ली के मेट्रो का कोई जवाब नहीं है। दिल्ली मेट्रो न केवल देश की राजधानी को हर कोने से जोड़ रही है। इसकी लंबाई तकरीबन 400 किलोमीटर है, जो पूरे देश के मेट्रो से कहीं ना कहीं ज्यादा है। अब दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने एक और नया इतिहास रचा है। हैदरपुर बादली मोड़ मेट्रो स्टेशन के पास अब तक का सबसे ऊंचा प्लेटफॉर्म का निर्माण पूरा हो चुका है। जी हां, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जहां से दिल्ली की तकरीबन सारी लाइन की ट्रेन मिल जाएंगी। मेट्रो ने फेज-IV के विस्तार के तहत मैजेटा लाइन एक्सटेंशन (जनकपुरी पश्चिम से आर.के. आश्रम मार्ग) कॉरिडोर में इंजीनियरिंग क्षेत्र की एक नई उपलब्धि हासिल की है।



पर 28.362 मी. ऊंचा प्लेटफॉर्म बनाया गया है। यह डीएमआरसी नेटवर्क का सबसे ऊंचा प्लेटफॉर्म बन गया है। इसने पिंक लाइन के धौला कुआं पर बने 23.6 मी. ऊंचाई के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। इस एलिवेटेड प्लेटफॉर्म को एक और खासियत यह है कि यहां पर 6 इंटरचेंज स्टेशन होंगे-

**पिरागढ़ी (ग्रीन लाइन के साथ)**

**मधुवन चौक (रेड लाइन के साथ)**

**हैदरपुर बादली मोड़ (येलो लाइन के साथ)**

**मजलिस पार्क (पिंक लाइन के साथ)**

**आजादपुर (येलो और पिंक लाइन के साथ)**

**आर के आश्रम मार्ग (ब्लू लाइन के साथ)**

**काफी चुनौती वाला काम**

इसका निर्माण काफी चुनौती पूर्ण रहा था जैसे कि स्ट्रक्चर को मजबूती

से बनाना, खंभों को ढलाई और पूर्व-निर्मित कॉम्पोनेंट को स्थापित करने के लिए सावधानी की जरूरी थी। इस परियोजना के एक महत्वपूर्ण कार्य के रूप में मौजूदा परिचालित येलो लाइन के ऊपर स्टील स्पैन का निर्माण किया जाना था। सुरक्षा व्यवस्था के साथ-साथ निर्माण कार्यों में व्यवधान न पड़े, इसके लिए इंजीनियरों ने स्ट्रेप-वाय-स्ट्रेप तरीके से कार्य को पूरा किया। खंभों का निर्माण तीन चरणों में किया गया, जिसमें कामगारों की सुरक्षा और कार्य में स्थिरता बनाए रखने के लिए सुरक्षा उपाय किए गए थे। चूँकि स्थान सीमित था, इसलिए पारंपरिक जमीनी सपोर्ट के बजाय मैकाले बार्स (Macalloy Bars) का उपयोग किया गया।

**दूसरा सबसे ऊंचा एलिवेटेड स्ट्रेच भी पूरा**

डीएमआरसी ने हैदरपुर बादली मोड़ मेट्रो स्टेशन के पास रेलवे क्रॉसिंग पर 52.288 मी. लंबे स्टील स्पैन का भी निर्माण पूरा कर लिया है। एलिवेटेड स्ट्रेच 27.610 मीटर ऊंचा है। दिल्ली मेट्रो में इस दूसरे सबसे ऊंचे एलिवेटेड स्ट्रेच की मेट्रो वायडवर्थ और चालू रेलवे ट्रैक के बीच स्थान की कमी के कारण जरूरी था। यह दो भारी-भरकम क्रेनों की मदद से बनाया गया है।

## दिल्ली में ट्रांसपोर्ट की स्थिति होगी और मजबूत....

### 11 हजार नई बसें सहित कई योजनाओं पर बोले मंत्री पंकज सिंह

दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने सरकार बनने के 2 दिन बाद ही बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने ना सिर्फ दिल्ली में महिलाओं की फ्री बस सेवा जारी रखने का आदेश दिया है, बल्कि 11 हजार नई इलेक्ट्रिक बसें लाने की भी बात कही है।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। दिल्ली में जब से भाजपा की सरकार बनी है, हर दिन दिल्ली वालों के लिए कुछ न कुछ खुशखबरी आ रही है। दिल्ली की नई सीएम रेखा गुप्ता समेत सभी 7 कैबिनेट मंत्री एकस्मर मोड में दिख रहे हैं। यमुना की सफाई से लेकर राजधानी में जारी अन्य प्रोजेक्ट को लेकर भी मंत्री एक्टिव दिख रहे हैं। इस बीच दिल्ली कैबिनेट के परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने बड़ा ऐलान कर दिया है। यह जनता के लिए बड़ा तोहफा होने वाला है।

**डेढ़ साल में लाई जाएंगी 11 हजार बसें - पंकज सिंह**

मोडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पंकज सिंह ने मोडिया से बात करते हुए दिल्ली में ट्रांसपोर्ट की स्थिति और मजबूत करने की बात कही है। पहले से लोगों को यह डर सता रहा था कि अगर भाजपा की सरकार आएगी तो दिल्ली में महिलाओं को मिलने वाली फ्री बस सेवा बंद हो जाएगी, लेकिन पंकज सिंह ने कहा कि यह योजना सुचारू रूप से चलती



रहेगी। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली में अगले डेढ़ साल के भीतर 11 हजार इलेक्ट्रिक बसें चलाने वाले हैं।

**50 फीसदी सीएनजी बसें को हटाया गया**

पंकज सिंह ने बताया वर्तमान में दिल्ली में 1,500 इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं। हम अगले डेढ़ साल में 11 हजार बसें और लेकर आएंगे, इसके अलावा सीएनजी बसें को बेड़े

से 50 प्रतिशत को बसों को हटा दिया गया है। बता दें कि दिल्ली की पूर्व सरकार आम आदमी पार्टी ने भी दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसों को चलाने पर खूब जोर दिया था। यही कारण है कि दिल्ली में सबसे अधिक इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं।

**दिल्ली में सबसे अधिक इलेक्ट्रिक वाहन**  
दिल्ली सरकार ने सिर्फ इलेक्ट्रिक बसों

पर ही ध्यान नहीं दिया है, बल्कि प्रदूषण से निपटने के लिए लोगों को भी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के सुझाव दिए हैं और इसमें कई प्रकार की योजना भी लेकर आई है। इसलिए दिल्ली में सबसे अधिक ई-व्हीकल का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, यह भी देश में सबसे अधिक है। इससे साफ है कि सिर्फ सरकार ही नहीं, बल्कि दिल्ली की आम जनता भी इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल कर रही है।

## दिल्ली लोक निर्माण मंत्री ने दिए सख्त आदेश, अब होगा दिल्ली की सड़कों का कायाकल्प

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली सरकार में लोक निर्माण मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने इसके लिए पहल शुरू कर दी है। जिसमें उन्होंने अधिकारियों को सड़कों के रखरखाव के साथ-साथ उनकी साफ-सफाई सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सड़कों को गह्रा मुक्त करने के साथ-साथ सड़कों पर साफ-सफाई और हरियाली भी सुनिश्चित की जाएगी। इस दौरान मंत्री ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर जोर दिया।



नई दिल्ली। आने वाले समय में दिल्ली में सड़कों के मामले में बड़ा बदलाव होने की उम्मीद है। दिल्ली सरकार में लोक निर्माण मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने इसके लिए पहल शुरू कर दी है। जिसमें उन्होंने अधिकारियों को सड़कों के रखरखाव के साथ-साथ उनकी साफ-सफाई सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए हैं।

उन्होंने कहा कि सड़कों को गह्रा मुक्त करने के साथ-साथ सड़कों पर साफ-सफाई

और हरियाली भी सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि वे अनावश्यक काम बंद करें और विकास कार्य सड़कों के रखरखाव के साथ-साथ अधिकतम लाभ मिल सके।

**सड़कें ऐसा बनें कि 10 से 15 साल टिकें**

उन्होंने कहा कि अभी देखा जा रहा है कि सड़कें एक-दो साल में खराब हो जाती थीं, कोई जवाबदेह नहीं होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, जवाबदेही तय होगी और सड़कें भी टिकेंगी। किसी भी तरह की अनियमितता पाए जाने पर किसी को बख्शा नहीं जाएगा।

**सड़कों को लेकर विभागों में बनेगा समन्वय**

सरकार के सभी विभागों में समन्वय भी बनाया जाएगा, नोडल अधिकारी बनाने की योजना है कि जिससे सड़कें बनाने के बाद उन्हें बार बार खोद दिए जाने से बचाया जा सके। मंत्री वर्माने साफ किया है कि सड़कों के निर्माण के मामले में विभागों में सामान्य भी जरूरी है।

उन्होंने कहा कि होता यह है कि सड़क बनने के बाद एक या दो महीने बाद दूसरा विभाग आ जाता है और सड़क को फिर से खोद दिया जाता है। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी सड़क बने तो पहले दूसरे विभागों को भी इस बारे में अवगत कराया जाए की आपात स्थिति के अलावा सड़क को खोजने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

Post

Parvesh Sahib Singh  
@p.sahibsingh

दिल्ली के बारापूला फेज-3 सराय काले खां से मयूर विहार तक ब्रिज निर्माण कार्य, वित्तीय व अन्य समस्याओं के कारण रुका हुआ था। आज PWD अधिकारियों और निर्माण कार्य देख रही L&T के अधिकारियों के साथ निरीक्षण कर पूरी जानकारी ली और उन्हें निर्माण कार्य को जल्द पूरे करने के दिशा निर्देश दिये।

हर कोने में बुनियादी सुविधाएं बेहतर हों और हमारा संकल्प है कि जनता को बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष न करना पड़े, क्षेत्र का निरंतर विकास हो। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी का नेतृत्व केवल सपने नहीं दिखाता, बल्कि उन्हें हकीकत में बदलने का कार्य भी करता है। हम आपके सहयोग से क्षेत्र के समग्र विकास हेतु प्रतिबद्ध हैं। जनकल्याण के ये कार्य नागरिकों को सुगम यातायात व स्वच्छ परिवेश प्रदान करेंगे।

Translate post



## सी एम रेखा गुप्ता प्रथम धर्मतीर्थ प्रवर्तन में शामिल होंगी



सुष्मा रानी

**नई दिल्ली।** राजधानी में प्रथम बार यमुना स्पोर्ट्स क्लब सूरजमल विहार में आयोजित हो रहे संघ शिरोमणि भाव लिंगी ज्ञान महोत्सव में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (24 फरवरी) जैन संतों से आशीर्वाद लेने आएंगी।

आयोजन के प्रवक्ता टीनू जैन ने यह जानकारी देते हुए बताया माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को आदिनाथ ज्ञान महोत्सव जीनागम पंथ दिवस में आमंत्रित

करने के लिए आयोजन समिति का एक प्रतिनिधि मंडल वरिष्ठ भाजपा नेता पंकज जैन के नेतृत्व में मिला और उन्हें इस कार्यक्रम का न्यौता दिया। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री ने आमंत्रण को सहर्ष स्वीकार करते हुए कहा कि वह विधानसभा की कार्यवाही से कुछ समय निकाल कर संत महामुनि विमर्श सागर एवं मंच पर मौजूद सभी जैन संतों का आशीर्वाद प्राप्त करने आने का पूर्ण प्रयास करेंगी।

आयोजन समिति से जुड़े टीनू जैन के

अनुसार इस प्रतिनिधि मंडल में शामिल संजय जैन, रविन्द्र जैन, राजीव जैन, राकेश जैन ने रेखा गुप्ता का स्वागत करते हुए उन्हें कार्यक्रम का आमंत्रणपत्र भेंट किया।

आयोजन समिति का दावा है इस ज्ञान महोत्सव में अरसी हज़ार से ज्यादा जैन श्रद्धालु शामिल होंगे। इस अवसर पर केशव एंड सोनू के स्वर संगीत कार्यक्रम विमर्श रत्न और रूपेश जैन मंच पर भजनो का कार्यक्रम पेश करेंगे।

## ‘आप’ सरकार ने 10 साल में दिल्ली का बजट 30 हजार करोड़ से ढाई गुना बढ़ाकर 77 हजार करोड़ रुपए तक पहुंचाया है - आतिशी

सुष्मा रानी

**नई दिल्ली।** दिल्ली की जनता से किए तमाम वादों को पूरा करने से बचने के लिए अभी से बहाने ढूँढने में जुटी भाजपा पर आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने रविवार को करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की खजाना खाली होने का बहाना न बनाए। जनता ने उसे जनादेश दिया है और अब वह दिल्लीवालों से किए अपने सारे वादे पूरा करे। उन्होंने कहा कि दस साल के शासन के बाद आम आदमी पार्टी ने भाजपा को आर्थिक रूप से विकसित और एक मजबूत सरकार सौंपी है। हमने 10 साल में दिल्ली का बजट 30 हजार करोड़ से ढाई गुना बढ़ाकर 77 हजार करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया है। भाजपा शासित एक भी राज्य नहीं है, जो दस साल में अपने बजट को ढाई गुना बढ़ा दिया हो और ऋण-जोड़ीपी अनुपात को 50 फीसद कम किया हो।

दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने कहा कि

मेरी यह अपेक्षा थी कि जिस दिन भाजपा की सरकार बनेगी वह सरकारी खजाना खाली होने का बहाना बनाकर अपने तथाकथित वादों और गारंटी को पूरा करने से बचेगी। भाजपा ने जो वादे दिल्लीवालों को किए, उनको पूरे नहीं करने के लिए ये लोग कोई न कोई बहाने जरूर बनाएंगे। इसलिए भाजपा की सरकार बनने से पहले और नई मुख्यमंत्री की शपथ लेने से पहले ही मैंने दिल्ली और पूरे देश के सामने दिल्ली के सरकारी खजाने के आंकड़े रख दिए थे।

उन्होंने बताया कि 2015 में जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, तब दिल्ली का कुल बजट मात्र 30 हजार करोड़ रुपए था। दिल्ली का बजट उसके अपने रिवेन्यू से आता है। हमारे अपने जीएसटी, एक्साइज कलेक्शन से आता है। दिल्ली को केंद्र सरकार से एक रुपया भी नहीं मिलता है। दस साल तक आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में एक ईमानदार और कुशल सरकार चलाई। इसके परिणाम



स्वरूप दिल्ली का जो बजट 2015 में 30 हजार करोड़ रुपए का था वह 2024-25 तक 77 हजार करोड़ रुपए का हो गया। यानी दस साल में दिल्ली का बजट 30 हजार करोड़ रुपए से बढ़कर 77 हजार करोड़ रुपए तक पहुंच गया। 10 साल में दिल्ली का बजट ढाई गुना से भी ज्यादा बढ़ गया है।

आतिशी ने भाजपा को चैलेंज देते हुए

कहा कि वह दिल्ली के अलावा अपने द्वारा शासित 20 राज्यों में से कोई भी एक राज्य बता दे, जहां 10 साल में उनकी सरकार का बजट ढाई गुना बढ़ गया हो। देश में भाजपा की कोई ऐसी सरकार नहीं है। किसी भी सरकार का वित्तीय स्वास्थ्य उसके ऋण-जोड़ीपी अनुपात से मापा जाता है। यानि उस राज्य के जोड़ीपी के अनुपात में उस सरकार

के ऊपर कितना कर्ज है? दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली के ऋण-जोड़ीपी अनुपात को आधा कर दिया है। पिछली सरकार से हमें 6 फीसद से ज्यादा ऋण-जोड़ीपी अनुपात मिला था। इसे आम आदमी पार्टी की सरकार ने मात्र तीन फीसद कर दिया। हमने दिल्ली को आज देश में सबसे कम ऋण-जोड़ीपी अनुपात पर लाकर खड़ा कर दिया है।

उन्होंने कहा कि 2022 की कैग रिपोर्ट में यह स्पष्ट लिखा है कि दिल्ली सरकार देश की एकमात्र ऐसी सरकार है जो 2015 से लेकर आज तक मुनाफे में चल रही है। देश में कोई और ऐसी सरकार नहीं है। आम आदमी पार्टी ने अपने 10 साल के शासन के बाद भाजपा को एक आर्थिक रूप से विकसित और मजबूत सरकार सौंपी है। मेरा भाजपा से निवेदन है कि दिल्ली की जनता ने बहुत भरोसा करके उसे जनादेश दिया है। भाजपा बहाने न बनाए, दिल्ली की लोगों ने उसपर जो भरोसा दिखाया है, वह उन वादों को पूरा करे।

## “आप” सरकार में हुए जनहित के कामों की रक्षा और भाजपा से उसके वादों को पूरा कराने की जिम्मेदारी आतिशी बखूबी निभाएंगी- गोपाल राय

सुष्मा रानी

**नई दिल्ली।** आम आदमी पार्टी ने रविवार को सर्वसम्मति से अपने विधायक दल का नेता चुन लिया। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और कालकाजी से विधायक आतिशी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष होंगी। नेता प्रतिपक्ष के चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक हुई। आतिशी नियुक्त ऑब्जर्वर डॉ. संदीप पाठक की मौजूदगी में विधायक संजीव झा ने नेता प्रतिपक्ष के रूप में आतिशी के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसका विधायक कुलदीप कुमार और जनरल सिंह ने समर्थन किया। इसके बाद पार्टी के सभी विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष के रूप में आतिशी के नाम पर अपनी सहमति दे दी। बैठक के बाद ‘आप’ के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सभी विधायकों से मुलाकात की और आतिशी को सर्वसम्मति में आम आदमी पार्टी का नेता चुने जाने पर बधाई देते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता के हित में रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएगी।

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक की अगुआई में हुई विधायक दल की बैठक के बाद दिल्ली प्रदेश संयोजक गोपाल राय और पूर्व सीएम आतिशी ने पार्टी मुख्यालय में प्रेसवार्ता की। गोपाल राय ने बताया कि पार्टी के नव

निर्वाचित विधायकों के साथ विधायक दल की बैठक की गई, जिसमें आम आदमी पार्टी के विधायक दल के नेता की चयन प्रक्रिया संपन्न हुई। इस प्रक्रिया के दौरान पार्टी ने सांसद डॉ. संदीप पाठक को ऑब्जर्वर नियुक्त किया था। डॉ. संदीप पाठक की उपस्थिति में विधायक संजीव झा ने पूर्व सीएम आतिशी को नेता प्रतिपक्ष बनाने का प्रस्ताव रखा। विधायक कुलदीप कुमार और जनरल सिंह ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। इसके बाद सभी विधायकों की राय ली गई और सर्वसम्मति से आतिशी को नेता प्रतिपक्ष बनाने के प्रस्ताव को पास किया गया। दिल्ली के लोगों के हित में जो काम किए हैं, पार्टी के विधायक दल का नेता चुना गया है। दिल्ली की जनता ने हमें विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया है। आतिशी दिल्ली विधानसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष की भूमिका का निर्वहन करेंगी।

गोपाल राय ने आगे कहा कि आम आदमी पार्टी के विधायक दल के नेता और सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष के रूप में आतिशी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगी। इससे पहले भी उन्होंने एक चुनौतीपूर्ण समय में दिल्ली की मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। साथ ही दिल्ली सरकार में मंत्री के रूप में भी काम कर चुकी हैं।

आम आदमी पार्टी की सरकार ने अब तक जनहित में जो काम किया है, हम उनकी रक्षा करेंगे। इसके अलावा, भाजपा ने दिल्ली की जनता से जो वादे किए हैं, जिनके आधार पर जनता ने उन्हें चुना है, अगर वह अपने वादे से मुकरते हैं, तो एक सशक्त और जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाते हुए आम आदमी पार्टी अपनी जिम्मेदारियां निभाएगी।

गोपाल राय ने कहा कि भाजपा ने दिल्ली की जनता से जो वादे किए हैं, उनको लागू करवाना और अब तक आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली के लोगों के हित में जो काम किए हैं, पार्टी के विधायक दल का नेता चुना गया है। दिल्ली के लोगों के हित में जो काम किए हैं, पार्टी के विधायक दल का नेता चुना गया है। दिल्ली के लोगों के हित में जो काम किए हैं, पार्टी के विधायक दल का नेता चुना गया है।

वहीं, दिल्ली की पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने पार्टी द्वारा भरोसा दिखाने और नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपने के लिए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पूर्व विधायक दल का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को विपक्ष की भूमिका में चुना है। एक मजबूत विपक्ष के रूप में आम आदमी पार्टी

सदन के अंदर पूरी ताकत से जनता की आवाज उठाएगी। भाजपा ने दिल्ली के लोगों को कई वादे किए, जिसके आधार पर जनता ने भाजपा को जनादेश दिया। एक विपक्ष के तौर पर यह हमारी जिम्मेदारी रहेगी कि भाजपा ने जनता से जो-जो वादे किए हैं, आम आदमी पार्टी एक विपक्ष के रूप में उन सभी वादों को पूरा करवाएगी।

आतिशी ने आगे कहा कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी ने पहला बड़ा वादा किया था कि कैबिनेट की पहली बैठक में दिल्ली की हर महिला को प्रति माह 2500 रुपए देने की योजना सरकार ने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली की जाएगी और 8 घण्टे तक पहली किस्त आ जाएगी। मोदी जी ने दिल्ली में प्रचार के दौरान यह वादा दे दिया था। लेकिन कैबिनेट की पहली बैठक हो गई और उसमें इस स्कीम पर चर्चा तक नहीं हुई। विपक्ष के तौर पर भाजपा की जवाबदेही तय करना आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी रहेगी। हम दिल्ली की महिलाओं से यह वादा करते हैं कि भाजपा और रेखा गुप्ता की सरकार ने दिल्ली की हर महिला को 2500 रुपए की जो गारंटी दी थी, हम उसे दिलवाकर रहेंगे।

आतिशी ने कहा कि विपक्ष के तौर पर हमारी पार्टी के दो महत्वपूर्ण एजेंडे रहेंगे। पहला, भाजपा ने जनता से जो वादे किए हैं, उन्हें पूरा करवाना, जिसमें प्रमुख तौर पर मोदी जी ने दिल्ली की

महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने की जो गारंटी दी थी, उसे लागू करवाना हमारे एजेंडे में सबसे ऊपर रहेगा। दूसरा, भाजपा के मंत्रियों के बयानों से ऐसा सुनने में आ रहा है कि अब तक आम आदमी पार्टी की सरकार और अरविंद केजरीवाल ने जो जनहितकारी काम किए हैं, उन्हें बंद कराने की कोशिश की जाएगी। अर्थात् दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का एक बयान आया था, जिसमें कई सारे मोहल्ला क्लीनिक बंद कराए जाएंगे। दिल्लीवालों का कहीं से भी कोई अहित न हो, इसके लिए हमारे सारे विधायक सदन से सड़क तक लड़ेंगे।

कैग की रिपोर्ट पर सदन में चर्चा को लेकर मीडिया सवाल का जवाब देते हुए आतिशी ने कहा कि उस कैग रिपोर्ट को मैंने बतौर मुख्यमंत्री विधानसभा अध्यक्ष को भेजी थी। इसलिए भाजपा जो यह बात फैला रही है कि उसने कैग रिपोर्ट पर निर्णय लिया है, दरअसल यह कैग की रिपोर्ट चुनाव से पहले ही सीलड लिफाफे में विधानसभा स्पीकर के पास चली गई थी। यह कैग रिपोर्ट सदन के पहले सत्र में प्रस्तुत होनी ही थी। इसलिए भाजपा जो यह भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है कि उसने सदन में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्णय लिया है, यह बिल्कुल भ्रामक है।

## एमसीडी की “आप” सरकार का ऐतिहासिक फैसला, 25 फरवरी को 12 हजार कच्चे कर्मचारी होंगे पक्का: आतिशी

मुख्य संवाददाता/ सुष्मा रानी

**नई दिल्ली।** दिल्ली नगर निगम में संविदा पर काम कर रहे हजारों कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुश खबर है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने एमसीडी के 12 हजार कच्चे कर्मचारियों को एक साथ पक्का करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। आगामी 25 फरवरी को आयोजित होने वाले एमसीडी के सदन में इन 12 हजार कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने पर मुहर लग जाएगी। यह जानकारी देते हुए ‘आप’ की वरिष्ठ नेता आतिशी ने बताया कि आम आदमी पार्टी ने एमसीडी चुनाव में कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का वादा किया था। अरविंद केजरीवाल के मार्गदर्शन में अब तक ‘आप’ की सरकार 4500 कच्चे सफाई कर्मियों को पक्का कर चुकी है। मुझे लगता है कि इस देश के इतिहास में आज तक किसी भी सरकार ने अपने एक निर्णय में एक साथ 12 हजार कच्चे कर्मचारियों को पक्का नहीं किया होगा।

आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता व पूर्व सीएम आतिशी ने नेता दुर्गेश पाठक, एमसीडी मेयर महेश खिंचो और सदन के नेता मुकेश गोयल के साथ रविवार को पार्टी मुख्यालय में प्रेसवार्ता कर इस ऐतिहासिक फैसले की जानकारी दी। आतिशी ने कहा कि आम आदमी पार्टी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए प्रतिबद्ध है। जिस दिन से आम आदमी पार्टी बनी है, यह आम आदमी पार्टी का वादा रहा है कि अलग-अलग सरकारी विभागों में काम कर रहे कच्चे कर्मचारियों को हमारी सरकार पक्का करेगी। इसी के तहत पंजाब में हमारी सरकार लगातार संविदा पर काम कर रहे शिक्षकों को पक्का कर रही है। दिल्ली में एमसीडी के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार ने अभी तक



4500 सफाई कर्मचारियों को पक्का कर चुकी है।

उन्होंने कहा कि अब इस कड़ी में आज आम आदमी पार्टी की एमसीडी सरकार एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। मुझे यह घोषणा करते हुए बहुत खुशी है कि आगामी 25 फरवरी को आयोजित होने वाले एमसीडी के सदन में 12 हजार कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। एमसीडी के इतिहास का यह सबसे बड़ा निर्णय होगा, जहां एक बार में 12 हजार कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। इसमें सभी विभाग के कच्चे कर्मचारी शामिल हैं। जिसमें सफाई कर्मचारी, माली, बेलदार, टीचर्स, इंजीनियरिंग विभाग में काम करने वाले डॉमैस्टिक ब्रीडर्स इत्यादि शामिल हैं।

आतिशी ने कहा कि एमसीडी के इतिहास में 25 फरवरी एक बड़ा दिन होगा, जहां 12 हजार कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। मुझे लगता है कि इस देश के इतिहास में आज तक किसी भी सरकार ने अपने एक निर्णय में एक साथ 12 हजार कच्चे कर्मचारियों को पक्का नहीं किया होगा। यह अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की सरकार है और हमने एमसीडी के 12 हजार कच्चे कर्मचारियों को पक्का करके उनके प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पूरा कर रहे हैं। जब हमने एमसीडी में चुनाव लड़ा था, तब हमने वादा किया था कि सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। आज मुझे खुशी है कि हम अपने इस वादे को पूरा कर रहे हैं।

इस दौरान एमसीडी मेयर महेश खिंचो ने

कहा कि आम आदमी पार्टी ने अब तक जो-जो वादे किए, सत्ता में आने के बाद उन सभी वादों को पूरा करके दिखाया। पिछले दो साल से दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार है। एमसीडी में हमने जो वादे किए थे, उसे पूरा करके दिखाया। पिछले दो साल में हमने करीब 4500 कर्मचारियों को पक्का किया है। अब आदमी पार्टी की सरकार को हम एमसीडी सदन में लगभग 12 हजार कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने जा रहे हैं। जिसमें अलग-अलग विभाग के माली, बेलदार, सफाई कर्मचारी, जूनियर इंजीनियर समेत कई कच्चे कर्मचारी पक्के किए जाएंगे। अरविंद केजरीवाल का एक ही मकसद है कि हम सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करें। उन्होंने जो वादा किया था, हम उसे पूरा करने जा रहे हैं।

## विधानसभा का पहला सत्र आज से, 25 को पेश होगी कैग रिपोर्ट; पहली बार एलजी करेंगे संबोधित

**नई दिल्ली।** दिल्ली विधानसभा का सोमवार से पहला सत्र शुरू होगा। दोनों पार्टियों ने सत्र के मद्देनजर अपनी रणनीति तय करने के लिए रविवार को अपने-अपने विधायक दल की बैठक की। 25 फरवरी को काफी समय से लंबित कैग की 14 रिपोर्ट पेश की जाएगी। सत्र 27 फरवरी तक चलेगा, जिसमें 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के अवसर पर कार्यवाही स्थगित रहेगी।

सोमवार को सभी विधायकों को प्रोटेम स्पीकर अरविंद सिंह लवली शपथ दिलाएंगे। इसके बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता विजेंद्र गुप्ता को स्पीकर पद के लिए चुना जाएगा। इसी तरह उपाध्यक्ष पद का भी चुनाव होगा। इस पद के लिए भाजपा ने अपने वरिष्ठ विधायक मोहन सिंह बिष्ट का नाम तय किया है।



**पहली बार विधानसभा को संबोधित करेंगे एलजी**  
25 फरवरी को सत्र का दूसरा दिन होगा। सबसे पहले उपराज्यपाल वीके सक्सेना मौजूद सरकार के कार्यकाल में पहली बार विधानसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद कैग की 14 रिपोर्ट भी रखी जाएंगी। कई रिपोर्ट 2016 से पेंडिंग हैं जिनमें दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण मसले हैं। विशेष रूप से इन रिपोर्टों में दिल्ली के आबकारी विभाग से जुड़े तथ्यों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिसमें शराब घोटाले के आरोपों की संभावना है। इसके अलावा, डीटीसी, मोहल्ला क्लीनिक, स्वास्थ्य विभाग और पब्लिक अंडरटेकिंग से जुड़ी रिपोर्ट भी पेंडिंग हैं।

**जनता की गाढ़ी कमाई का हिसाब पिछली सरकार को देना होगा: रेखा गुप्ता**  
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को कहा कि जनता की जिस गाढ़ी कमाई का दुरुपयोग पिछली सरकार ने किया है, उसका हिसाब उन्हें अब दिल्ली की जनता को देना पड़ेगा। अब दिल्ली में विकास की नई नींव रखने जा रही है। सरकार का एक ही एजेंडा है दिल्ली को विकसित राजधानी बनाना। तीन दिवसीय विधानसभा सत्र में विकास की योजनाओं पर चर्चा होगी। पहले ही सदन में सीएजी रिपोर्ट को पटल पर रखा जाएगा।

**आतिशी होंगी नेता प्रतिपक्ष**

आप ने पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी को विधायक दल का नेता चुना है। इसका फैसला रविवार को विधायक दल की बैठक में हुआ। पार्टी की तरफ से नियुक्त पर्यवेक्षक डॉ. संदीप पाठक की मौजूदगी में विधायक संजीव झा ने नेता प्रतिपक्ष के रूप में आतिशी के नाम का प्रस्ताव रखा। विधायक कुलदीप कुमार और जनरल सिंह ने इसका समर्थन किया। इसके बाद पार्टी के सभी विधायकों ने आतिशी के नाम पर सहमति दे दी।



# मर्सिडीज की कारों में मिली बड़ी खामी, कंपनी ने जारी किया रि कॉल, जानें क्या आपकी कार तो लिस्ट में शामिल नहीं

परिवहन विशेष न्यूज

जर्मनी की लग जरी वाहन निर्माता Mercedes Benz की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। रिपोटर्स के मुताबिक कंपनी की कई कारों में गड़बड़ी मिली है। जिसके बाद प्रभावित कारों के लिए Recall को जारी किया गया है। मर्सिडीज की किन कारों में किस तरह की गड़बड़ी मिली है। कितनी प्रभावित यूनिट्स को वापस बुलाया गया है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। देश में सामान्य कारों के साथ ही कई विदेशी कंपनियों की कारों को भी पसंद किया जाता है। कई लगजरी कारों को ऑफर करने वाली

जर्मन निर्माता Mercedes Benz की कारों में गड़बड़ी की जानकारी सामने आई है। जिसके बाद कंपनी ने इन कारों के लिए Recall जारी किया है। कंपनी को इन कारों की कितनी यूनिट्स के लिए किस तरह की गड़बड़ी की जानकारी मिलने के बाद रि कॉल (Mercedes Benz Recall 2025) को जारी किया है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

**Mercedes ने जारी किया Recall**  
मर्सिडीज बेंज की ओर से कई कारों के लिए रि कॉल को जारी किया गया है। रिपोटर्स के मुताबिक कंपनी की ओर से अलग अलग समस्याओं की जानकारी सामने आने के बाद इन कारों के लिए रि कॉल को जारी किया है।

कितनी यूनिट्स के लिए जारी हुआ रि कॉल

रिपोटर्स के मुताबिक कंपनी की ओर से करीब 2546 यूनिट्स के लिए रि कॉल को जारी किया गया है। इन यूनिट्स में इसी यू की परेशानी की जानकारी सामने आई है। इसके अलावा 96 यूनिट्स के लिए भी अलग से रि कॉल किया गया है। इन कारों में फ्यूल डिलीवरी मॉड्यूल में समस्या के बाद वापस बुलाया गया है।

**कौन से मॉडल हुए प्रभावित**  
जानकारी के मुताबिक कंपनी की किन कारों में ये समस्याएं पाई गई हैं उनमें E-Class, C-Class, GLC, S-Class, G-Class, AMG GT, AMG G63 जैसी कारें और एसयूवी



शामिल हैं।

**कब बनी हैं यूनिट्स**  
मर्सिडीज की ओर से ई-क्लास कारों को ऑफर किया जाता है। इसकी प्रभावित यूनिट्स को 29 अप्रैल 2022 से 20 अगस्त 2024 के बीच बनाया गया है। जिनमें सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी पाई गई है। वहीं सी-क्लास की प्रभावित यूनिट्स को

31 अगस्त 2021 से 20 अगस्त 2024 के बीच बनाया गया है।

GLC की यूनिट्स को सात अक्टूबर 2022 से अब तक बनाया जा रहा है। एस-क्लास की यूनिट्स को 20 जुलाई 2022 से 29 सितंबर 2023, जी-क्लास की यूनिट्स को 17 अगस्त 2022 से 20 दिसंबर 2022, AMG GT की

यूनिट्स को पांच अक्टूबर 2022 से अभी तक और AMG G63 की यूनिट्स को नौ अक्टूबर 2021 से 18 अक्टूबर 2022 के बीच बनाया गया है। इन कारों में फ्यूल डिलीवरी मॉड्यूल की समस्या की जानकारी सामने आई है।

**कंपनी दे रही जानकारी**

मर्सिडीज की ओर से किन यूनिट्स में खराबी की जानकारी सामने आई है। उन लोगों को ई-मेल, फोन के जरिए जानकारी दी जा रही है।

**बिना चार्ज ठीक होगी कारें**  
जिन भी यूनिट्स में खराबी पाई गई है, उनको सर्विस सेंटर पर ले जाना होगा। जहां उनकी खराबी को बिना कोई अतिरिक्त चार्ज लिए ठीक किया जाएगा।

# नई गाड़ी खरीदने पर लाखों की बचत का आखिरी मौका, इन कारों पर मिलेगा सबसे ज्यादा डिस्काउंट

परिवहन विशेष न्यूज

वाहन निर्माताओं की ओर से अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए हर महीने कई Discount Offers अपनी कारों पर दिए जाते हैं। February 2025 में भी कई कारों पर लाखों रुपये के ऑफर्स दिए जा रहे हैं। अगर आप भी इस महीने नई गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो 28 फरवरी तक किन कारों पर सबसे ज्यादा बचत की जा सकती है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। वाहन निर्माताओं की ओर से हर महीने अपने पोटफोलियो की कारों पर तगड़े डिस्काउंट ऑफर्स दिए जाते हैं। अगर इस महीने अभी तक आप गाड़ी नहीं खरीद पाए हैं तो 28 February 2025 तक किन Cars and SUVs को खरीदने पर लाखों रुपये बचाए जा सकते हैं। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

**हुंडई Ioniq5 पर चार लाख रुपये की बचत का मौका**

साउथ कोरियाई वाहन निर्माता Hyundai की ओर से भारतीय बाजार में कई बेहतरीन कारों और एसयूवी की बिक्री की जाती है। कंपनी प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी के तौर पर Hyundai Ioniq5 को ऑफर करती है। अगर आप भी इस महीने इस गाड़ी को खरीदते हैं तो आपको अधिकतम चार लाख रुपये तक की बचत हो सकती है। कंपनी की ओर से केश बैंनिफिट के तौर पर इसकी 2024 की यूनिट्स पर यह ऑफर दिया जा रहा है। इसकी एक्स शोरूम कीमत 46.05 लाख



रुपये है।

**Maruti Invicto पर 2.45 लाख रुपये की बचत का मौका**

मारुति की ओर से सबसे महंगी गाड़ी के तौर पर MPV सेगमेंट में Maruti Invicto को लाया जाता है। 2024 की बची हुई यूनिट्स को फरवरी के आखिर तक खरीदने पर आपको 2.45 लाख रुपये तक की बचत का मौका दिया जा रहा है। यह ऑफर इसके टॉप वेरिएंट Alpha पर मिलेगा। इसकी एक्स शोरूम कीमत 25.51 लाख रुपये से शुरू होती है।

**ग्रेड विटारा पर दो लाख से ज्यादा की बचत का मौका**

फरवरी 2025 के बचे हुए दिनों में अगर Maruti Grand Vitara को खरीदा जाता

है तो आप अपने 2.18 लाख रुपये तक बचा सकते हैं। एसयूवी के ऑल व्हील ड्राइव की 2024 की यूनिट्स पर यह बचत की जा सकती है। कंपनी इस एसयूवी पर केश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, रूरल ऑफर्स के तहत यह ऑफर दे रही है। इसकी एक्स शोरूम कीमत 11.09 लाख रुपये से शुरू होती है।

**Maruti Jimny पर मिलेगा तगड़ी बचत का मौका**

फरवरी 2025 में अगर आप मारुति की जिम्नी के टॉप वेरिएंट Alpha को खरीदने जा रहे हैं, तो इसकी 2024 की यूनिट्स पर इस महीने में 1.91 लाख रुपये तक बचाए जा सकते हैं। कंपनी की ओर से पिछले साल की बची यूनिट्स पर केश डिस्काउंट के साथ ही

बुकिंग ऑफर के तहत यह ऑफर दिया जा रहा है। वहीं इसके Zeta वेरिएंट पर इस महीने 1.20 लाख रुपये की बचत हो सकती है। इसकी एक्स शोरूम कीमत 12.76 लाख रुपये से शुरू होती है।

**Honda Amaze पर भी होगी बचत**

होंडा की ओर से कॉम्पैक्ट सेडान कार के तौर पर अमेज को लाया जाता है। इसकी दूसरी जेनरेशन पर कंपनी इस महीने 1.07 लाख रुपये के ऑफर दे रही है। पुरानी अमेज के टॉप वेरिएंट VX पर यह ऑफर दिया जा रहा है। इसके अन्य वेरिएंट्स पर 57 हजार रुपये तक बचाए जा सकते हैं। पुरानी जेनरेशन अमेज की एक्स शोरूम कीमत 7.20 लाख रुपये से शुरू होती है।

# चलाने में है कितनी दमदार, क्या है प्रेक्टिकल कार, खरीदने में होगा फायदा या नुकसान

परिवहन विशेष न्यूज

ब्रिटेन की कार कंपनी MG मोटर्स भारत में सबसे नई EV के तौर पर MG Windsor EV को ऑफर करती है। कंपनी की यह गाड़ी हमने कुछ दिनों के लिए चलाई। इस दौरान हमने इसे कई मायनों में परखा। व या यह सच में एक दमदार ईवी है। ट्रैफिक और खुली सड़कों पर यह कितनी प्रेक्टिकल कार है। व या इसे खरीदने में फायदा होगा? आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। दुनियाभर के साथ ही भारत में भी EV की काफी मांग है। महंगे कारों के साथ बजट वाले ईवी सेगमेंट में भी Tata, Mahindra और MG अपनी कारें ऑफर करते हैं। ऐसे ही MG Windsor EV को भी 10 से 16 लाख रुपये के बीच ऑफर किया जाता है। हमने करीब पांच दिन इस CUV को चलाकर देखा। इस दौरान शहर के ट्रैफिक के साथ ही हाइवे पर भी इसे चलाया। मिडल क्लास फैमिली के लिए यह कार कितनी प्रेक्टिकल है। किस तरह के फीचर्स इसमें मिलते हैं। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

**कैसी है MG Windsor EV**

एमजी की ओर से बजट ईवी के तौर पर MG Windsor EV को 2024 में ही लॉन्च किया गया था। पिछले साल के फेस्टिव सीजन से



इसकी डिलीवरी को देना शुरू किया गया था। जिसके बाद से ही यह गाड़ी लोगों को काफी पसंद आ रही है। ऐसे में हमने भी इस गाड़ी को परखने की कोशिश की जिससे यह समझ सकें कि आखिर काफी कम समय में ही यह गाड़ी भारतीयों की पसंद कैसे बन रही है। हमने इसे करीब पांच दिन शहर के ट्रैफिक के साथ ही हाइवे की खुली सड़कों पर दिन और रात के समय चलाकर देखा। इस दौरान हमने यह समझने की कोशिश की कि क्या यह गाड़ी एक मिडल क्लास परिवार के लिए कितनी प्रेक्टिकल कार हो सकती है।

**कैसा है डिजाइन**

एमजी ने Windsor EV को एक फ्यूचरिस्टिक डिजाइन के साथ ऑफर किया है। कंपनी के मुताबिक इसके फ्रंट को किसी प्लेन के फ्रंट के कार के मुकाबले ज्यादा एयरी लगता है।

लोगों को यह डिजाइन पसंद भी आया और कुछ लोग इसे और बेहतर करने की बात भी कह सकते हैं। लेकिन हमें भी इसका डिजाइन काफी अच्छा लगा और तकनीकी तौर पर बात करें तो तेज स्पीड में जब इसे चलाया जाता है तो यह डिजाइन एयरोडायनामिक होने के कारण ज्यादा बेहतर तरीके से कार चलाने में मदद करता है। साइड प्रोफाइल में दिए इसके दरवाजे काफी चौड़े हैं जिस कारण गाड़ी में बैठने और बाहर निकलने में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होती। रियर से भी इसका लुक काफी बेहतर बनाया गया है। रात के समय गाड़ी का फ्रंट और रियर काफी बेहतर लगता है। गाड़ी में विंडो काफी बड़ी दी गई है साथ ही पैनोरमिक सनरूफ के कारण केबिन अन्य कारों के मुकाबले ज्यादा एयरी लगता है।

# ट्रैफिक पुलिस ने काट दिया गलत चालान, कहां और किससे करें शिकायत? जानिए



परिवहन विशेष न्यूज

अगर आपके वाहन का चालान गलती से कट गया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से इसकी शिकायत कर सकते हैं और गलत जुर्माने से बच सकते हैं।

कई बार वाहन चालकों के साथ ऐसा होता है कि उनका गलत चालान कट जाता है। यह कभी सीसीटीवी कैमरे की गड़बड़ी की वजह से होता है, तो कभी ट्रैफिक पुलिस की गलती से। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर किसी का गलत चालान कट जाए, तो इसकी शिकायत कहां और कैसे करें?

अगर आपके वाहन का चालान गलती से कट गया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों

तरीकों से इसकी शिकायत कर सकते हैं और गलत जुर्माने से बच सकते हैं। आइए जानते हैं शिकायत करने की पूरी प्रक्रिया।

**ऑनलाइन शिकायत कैसे करें?**

अगर आप घर बैठे अपना गलत चालान रद्द करवाना चाहते हैं, तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

1. सबसे पहले [morth.nic.in](http://morth.nic.in) पर जाएं।
2. वहां रेशिकायत (Grievance) विकल्प पर क्लिक करें।
3. अब अपनी जानकारी जैसे नाम, मोबाइल नंबर और चालान नंबर भरें।
4. सभी विवरण भरने के बाद शिकायत सबमिट करें।
5. अगर आपको शिकायत

सही पाई जाती है, तो चालान रद्द किया जा सकता है।

ऑफलाइन शिकायत कैसे करें?

अगर आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज नहीं करना चाहते, तो ट्रैफिक पुलिस स्टेशन या हेल्पलाइन नंबर की मदद ले सकते हैं। इसके लिए आपको अपने नजदीकी ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत दर्ज कराना होगा। आप अपने क्षेत्र की ट्रैफिक पुलिस हेल्पलाइन पर कॉल कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

अगर आप दिल्ली में रहते हैं, तो अपनी शिकायत [info@delhitrafficpolice.nic.in](mailto:info@delhitrafficpolice.nic.in) पर ईमेल कर सकते हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के कंट्रोल रूम नंबर 11-2584-4444 या 1095 पर कॉल करके भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

# कब ब्लैक लिस्ट हो सकता है फास्टैग, कितना रखना होगा मिनिमम बैलेंस? जानिए क्या है नया नियम



इतने बैलेंस पर फास्टैग हो जाएगा ब्लैकलिस्ट

परिवहन विशेष न्यूज

NPCI ने 28 जनवरी 2025 को एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें FASTag से जुड़े अहम बदलाव किए गए हैं। आइए जानते हैं नए नियमों के बारे में और यह भी समझते हैं कि कब आपका FASTag ब्लैकलिस्ट हो सकता है।

अगर आप भी हाइवे पर सफर करते हैं और टोल प्लाजा पर FASTag का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लिए यह खबर बेहद जरूरी है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने FASTag को लेकर नए नियम लागू कर दिए हैं, जो 17 फरवरी 2025 से प्रभावी हो गए हैं। इन नियमों का मकसद टोल वसूली को आसान बनाना और ट्रैफिक को सुचारू बनाए रखना है। आइए जानते हैं नए नियमों के बारे में और यह भी समझते हैं कि कब

आपका FASTag ब्लैकलिस्ट हो सकता है।

**नए नियमों के तहत क्या बदला?**

NPCI ने 28 जनवरी 2025 को एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें FASTag से जुड़े अहम बदलाव किए गए हैं। नए नियमों के मुताबिक, अगर आपका FASTag ब्लैकलिस्ट हो जाता है और आप टोल प्लाजा पर पहुंचने के बाद उसे रिचार्ज करते हैं, तो वह तुरंत एक्टिव नहीं होगा। टोल प्लाजा पर खड़े होकर रिचार्ज करने से भी आपको कोई मदद नहीं मिलेगी और आपको फाइन के रूप में दोगुना टोल भरना पड़ सकता है।

अब, अगर आपको ब्लैकलिस्टिंग से बचना है, तो आपको FASTag रीड होने से 60 मिनट पहले या फिर रीड होने के 10 मिनट के भीतर रिचार्ज करना होगा। अगर आप इस विंडो में रिचार्ज कर लेते हैं, तो आपसे दोगुना चार्ज नहीं लिया जाएगा।

FASTag ब्लैकलिस्ट होने के पीछे कई वजहें हो सकती हैं। अगर समय रहते आप इन चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं, तो आपको सफर के दौरान दिक्कत हो सकती है। आइए जानते हैं किन कारणों से आपका FASTag ब्लैकलिस्ट हो सकता है:

1. FASTag वॉलेट में कम बैलेंस होने पर।
2. बार-बार टोल शुल्क का भुगतान न करने पर।
3. पेमेंट फेल होने की स्थिति में।
4. KYC अपडेट न होने पर।
5. गाड़ी के चेसिस नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर में गड़बड़ी होने पर।

कितना रखना होगा मिनिमम बैलेंस? What Minimum Balance Should Be Kept In FasTag How Fastag is Blacklisted NHAI ने FASTag वॉलेट में न्यूनतम बैलेंस रखने के नियम को हटा दिया

है, लेकिन सफर के दौरान परेशानी से बचने के लिए आपको कम-से-कम 100 रुपये का बैलेंस जरूर रखना चाहिए। इससे न सिर्फ आपकी यात्रा सुगम होगी, बल्कि ब्लैकलिस्टिंग जैसी परेशानियों से भी बच सकेंगे।

**ब्लैकलिस्टिंग से बचने के लिए क्या करें?**

1. FASTag अकाउंट में कम से कम 100 रुपये का बैलेंस जरूर रखें।
2. बैंक से आने वाले मैसेज और नोटिफिकेशन पर ध्यान दें।
3. MyFastag एप इंस्टॉल करें और अपने फास्टैग स्टेटस को रेगुलर चेक करें।
4. फास्टैग से जुड़े मोबाइल नंबर को हमेशा एक्टिव रखें।
5. टोल भुगतान में कोई गड़बड़ी हो तो तुरंत संबंधित बैंक से संपर्क करें।
6. चेक करें कि फास्टैग कहीं कटा-फटा न हो।



विजय गर्ग

# शानदार सफलता का स्क्रिल है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट

पहले, किसी योजना को अंजाम देने के लिए अलग-अलग विभाग काम करते थे, जिससे काम में उलझनें और देरी होती थी। अब प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर एक व्यक्ति योजना से जुड़े सभी लोगों को साथ लेकर चलता है, प्लान बनाता है, संसाधन इकट्ठा करता है, और ये देखता है कि सब कुछ ठीक से हो रहा है या नहीं टीम बनाना, फाइनेंस की व्यवस्था और बजटिंग, जरूरी बदलाव और क्वालिटी का ध्यान रखना भी उसकी जिम्मेदारी होती है।

तेज औद्योगिक विकास के इस दौर में विभिन्न उद्योगों में नई परियोजना की शुरुआत होना नई बात नहीं है नया है वर्तमान में ऐसे नए प्रोजेक्ट्स की बहुतायत और इन्हें पूरा करने का तरीका। अब अधिकतर कंपनियां अपनी परियोजनाओं के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर्स की मदद लेती हैं। इसी के चलते प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के स्क्रिल का काम भी खूब बना है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट कहती है कि आने वाले 2030 तक कंपनियों को प्रति वर्ष 20 लाख प्रोजेक्ट मैनेजर्स को नियुक्त करने की जरूरत होगी। वहीं फोर्ब्स पत्रिका के एक लेख के अनुसार व्यापारिक प्रतियोगिता और तेज विकास के इस दौर में विविध उद्योगों में वैश्विक स्तर पर लगभग 2.5 करोड़ प्रोजेक्ट मैनेजर चाहिए होंगे आने वाले कुछ वर्षों में। इसी संदर्भ में एंडरसन एनालिसिस ग्रुप की एक टेलेंट गैप एनालिसिस के अनुसार वैश्विक स्तर पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में रोजगार के कुल 75 फीसदी का प्रतिनिधित्व भारत और चीन करेंगे। कहने की जरूरत नहीं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का क्षेत्र आपको एक अच्छा भविष्य देने में पूरी तरह सक्षम है। यहां एंटी लेवल पर भी सालाना 9 लाख से ज्यादा सैलरी मिल सकती है। वहीं 5 साल के अनुभव के बाद आपको 18 लाख रुपये प्रति वर्ष तक का वेतन मिल सकता है। देश-विदेश में नेटवर्किंग के मौके भी मिलते हैं।

क्या होता है काम



पहले, किसी योजना को अंजाम देने के लिए अलग-अलग विभाग काम करते थे, जिससे काम में उलझनें और देरी होती थी। अब प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर एक व्यक्ति योजना से जुड़े सभी लोगों को साथ लेकर चलता है, प्लान बनाता है, संसाधन इकट्ठा करता है, और ये देखता है कि सब कुछ ठीक से हो रहा है या नहीं टीम बनाना, फाइनेंस की व्यवस्था और बजटिंग, जरूरी

बदलाव और क्वालिटी का ध्यान रखना भी उसकी जिम्मेदारी होती है।

क्या हो रोजमैप

बिजनेस, इंजीनियरिंग, आईटी या संबंधित क्षेत्र में बैचलर्स डिग्री लें। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल (PMP) सर्टिफिकेशन करें। इंटरशिप करें लीडरशिप और कम्यूनिक्शन स्किल्स बेहतर करें। दूसरे प्रोजेक्ट मैनेजर्स और

एम्प्लॉयर्स से संपर्क बनाएं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया से प्रोफेशनल नेटवर्क बढ़ाएं।

तकनीकी स्क्रिलसेट

प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अप्रॉच (जैसे एजाइल, वाटरफॉल) और टूल्स (जैसे MS Project, Jira, Trello) की समझ होनी चाहिए। फोर्ब्स के एक लेख की मांनें, तो एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में

दक्षता आपको आयु क्षमता को 47 फीसदी बढ़ा देंगे। इसके लिए Coursera और Skillsoft अच्छे संच हैं। वहीं बिजनेस एनालिसिस का स्क्रिल इसमें अहम होता है और उनकी आयु में 43 फीसदी तक बढ़ोतरी कर सकता है। रिस्क मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के सर्टिफिकेशन भी मदद करेंगे। ये वैश्विक स्तर पर मान्यताप्राप्त हैं। कितने तरह के अवसर

सरकारी और निजी, दोनों सेक्टर में मौके मिलते हैं। आईटी सेक्टर में ये भूमिका सबसे ज्यादा है। आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सिस्टम अपग्रेड और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स देखते हैं। आईटी, इन्फॉर्मेशन साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बैचलर्स के लिए। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजर आर्किटेक्चर, सिविल इंजीनियरिंग आदि से संबंधित डिग्री के युवाओं के लिए। ये बड़े स्तर के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर रिहायशी प्रोजेक्ट्स तक पर काम करते हैं। हेल्थकेयर प्रोजेक्ट मैनेजर्स: इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड सिस्टम, हेल्थकेयर फैसिलिटी निर्माण या नई तकनीक के प्रोजेक्ट पर काम करना होगा। हेल्थकेयर एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री काम आएगी। इसी तरह मार्केटिंग प्रोजेक्ट मैनेजर, रिटेल और कंज्यूमर गुड्स प्रोजेक्ट मैनेजर भी होते हैं।

काम के शुरुआती सर्टिफिकेशन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल (PMP) सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और मान्यताप्राप्त सर्टिफाइड असोसिएट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट (CAPM) सर्टिफाइड प्रोजेक्ट मैनेजर (CPM) एजाइल सर्टिफाइड प्रैक्टिशियन (ACP) कॉम्प्लैट प्रोजेक्ट कुछ काम के कोर्स ऑनपरेशनल रिस्क मॉडेलिंग, अकाउंटिंग फंडामेंटल्स ट्रेनिंग कोर्स, आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एसेसियल

## लिव-इन रिलेशनशिप को मान्यता कितनी जायज़?

— डॉ. सत्यवान सौरभ

लिव-इन रिलेशनशिप के मुश्किल से 10% मामलों ही शादी तक पहुंच पाते हैं। बाकी 90% मामलों में रिश्ते टूट ही जाते हैं। ठीक उसी तरह, जिस तरह आजकल के नवयुवक प्रेमी-प्रेमिकाएँ जितनी तेजी से प्रोपोज करते हैं उतनी ही तेजी से ब्रेकअप और फिर उतनी ही तेजी से प्रेमी भी बदल लेते हैं। ऐसे प्रेमी-प्रेमिकाओं को लिव-इन रिलेशनशिप जैसी लुभावनी प्रथा सही लगती है। क्योंकि उन्हें एक दूसरे के साथ बिना शादी के पति-पत्नी जैसा रहने का मौका मिल जाता है और पति-पत्नी जैसे रिश्ते का अर्थ आप अच्छी तरह समझते हैं। इसीलिए रिश्ता टूटने के बाद सबसे ज्यादा जीवन बर्बाद लड़कियों का होता है। विशेषकर विवाह के समान भरण-पोषण और उत्तराधिकार के अधिकार प्रदान करना। सहवास में जन्मे बच्चों की कानूनी स्थिति को स्पष्ट करना, विशेष रूप से वैधता और उत्तराधिकार अधिकारों के सम्बंध में। रिश्ता टूटने के बाद अक्सर लड़कियाँ आत्महत्या जैसे क्रदम उठा लिया करती हैं।

वैश्वीकरण के प्रभाव और पश्चिमी संस्कृति के संपर्क में आने के कारण अब लिव-इन रिलेशनशिप को अधिक स्वीकार्य माना जाने लगा है। यह सहवास के नैतिक परिणामों तथा विवाह और परिवार के पारंपरिक विचारों पर प्रश्न उठाता है। भारतीय युवाओं की जीवन शैली में तेजी से बदलाव आ रहा है। इसके लिए ये आधुनिक संस्कृति को अपनाने में कोई भी झिझक महसूस नहीं करते और लिव इन

रिलेशनशिप आधुनिक संस्कृति की ही एक शैली है। आजकल के युवा लिव इन रिलेशनशिप को वैवाहिक जीवन से बेहतर मानने लगे हैं। आज की पीढ़ी शादी और लिव इन रिलेशनशिप को एक जैसा ही मानती है। इनका मानना है कि शादी में समाज और कानून का हस्तक्षेप होता है किन्तु लिव इन रिलेशनशिप में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बल्कि पूरी आजादी होती है। लेकिन शादी और लिव इन रिलेशनशिप में अंतर है। ये प्रथा जितनी आसान लगती है उतनी ही पेचीदा है। जितने इसके फायदे हैं उतने ही ज़्यादा नुकसान हैं। इस तरह के सम्बंध प्रायः पश्चिमी देशों में बहुतायत में देखने मिलते हैं। क्योंकि वहाँ की संस्कृति इस प्रथा को सहज ही स्वीकार करती है। वहाँ की लाइफस्टाइल भी कुछ इसी तरह की है। भारत में भी कुछ वर्षों से इस व्यवस्था को सपोर्ट मिला है। जिसके पीछे महानगरों में बसने वाले कुछ लोगों के बदलते सामाजिक विचार, विवाह की समस्या और धर्म से जुड़े मामलों का होना माना जा सकता है। समाज का एक वर्ग इसे भारतीय संस्कृति के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है। तो वहीं दूसरा वर्ग इसे आधुनिक परंपरा में बदलाव के रूप में देखते हुए स्वतन्त्र जीवन जीने के लिए वरदान मानता है। हर चीज़ के अपने-अपने फायदे और नुकसान होते हैं।

हाल ही में अधिनियमित उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (यूसीसी) ने लिव-इन पार्टनरशिप के लिए व्यापक विनियमों की एक श्रृंखला स्थापित की, जिसका लक्ष्य उन्हें

विनियमित करना और उनकी कानूनी मान्यता की गारंटी देना है। लेकिन इनसे काफ़ी चर्चा भी हुई है और सरकारी निगरानी तथा गोपनीयता को लेकर चिंताएँ भी पैदा हुई हैं। पिछले 20 वर्षों में, लिव-इन रिलेशनशिप-जिसमें जोड़े बिना शादी किए एक साथ रहते हैं-भारतीय समाज और कानून में अधिक स्वीकार्य हो गए हैं। अतीत में भारतीय समाज पारंपरिक मूल्यों पर आधारित था और प्रतिबद्ध रिश्ते का एकमात्र स्वीकृत रूप विवाह था। लिव-इन पार्टनरशिप को अक्सर कलंकित माना जाता था तथा समाज द्वारा इसे नकारात्मक दृष्टि से देखा जाता था। हालाँकि, वैश्वीकरण के प्रभाव और पश्चिमी संस्कृति के संपर्क में आने के कारण अब लिव-इन रिलेशनशिप को अधिक स्वीकार्य माना जाने लगा है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार (अनुच्छेद 14, 19, 21) का उपयोग करते हुए, भारतीय अदालतों ने कई फैसलों में लिव-इन रिश्तों को मान्यता दी है। कन्यामल्ल (2010) के अनुसार, लिव-इन पार्टनरशिप व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आती है। सरमा, इंद्र वि। 3, के. वी.। सरमा (2013) : इसने धरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 (पीडब्ल्यूडीवीए) के तहत विवाह जैसे दिखने वाले लिव-इन रिश्तों को मान्यता दी और उन्हें विधिन प्रकारों में वर्गीकृत किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने रेखांकित किया है कि साथी चुनने और घनिष्ठ सम्बंध स्थापित करने की स्वतंत्रता संविधान के मुक्त

भाषण और अभिव्यक्ति पर अनुच्छेद 19 (सी) के अंतर्गत आती है। धरेलु हिंसा के विरुद्ध संरक्षण अधिनियम, 2005 (पीडब्ल्यूडीवीए) अपने दायरे में रविवाह की प्रकृति वाले सम्बंधों को शामिल करके, लिव-इन सम्बंधों में धरेलु हिंसा का सामना करने वाली महिलाओं को संरक्षण प्रदान करता है। डी. वेलुसामी बनाम के सम्बंध में। न्यायालय ने डी. पंचअम्मल (2010) में फैसला सुनाया कि केवल विवाह जैसे रिश्ते ही धरेलु हिंसा कानूनों के तहत कानूनी संरक्षण के लिए योग्य होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने उन मामलों में व्यवस्था दी है जहाँ लिव-इन रिलेशनशिप से जन्मे बच्चों को कानूनी रूप से विवाहित माता-पिता के समान उत्तराधिकार के अधिकार प्राप्त होंगे। उत्तराखंड यूसीसी के तहत लिव-इन पार्टनरशिप का पंजीकरण होना आवश्यक है। यह उत्तराखंड के निवासियों और भारत के बाहर रहने वाले लोगों दोनों पर लागू है। जो जोड़े एक साथ रहने का अयोग्य नहीं हैं। कानूनी रिश्ते को यूसीसी के तहत शुरू और अंत में पंजीकृत करना होगा। यदि वे औपचारिक रूप से अपने रिश्ते को स्थापित करना चाहते हैं, तो विवाह के लिए युगल की पात्रता की पुष्टि करने वाला धार्मिक नेता से प्राप्त प्रमाण पत्र, आधार से जुड़ा ओटीपी, तथा पंजीकरण शुल्क, सहायक दस्तावेजों के साथ आ सकते हैं। यूसीसी अधिनियम के तहत 74 प्रकार के सम्बंधों पर प्रतिबन्ध है, जिनमें से 37 पुरुषों के लिए तथा 37 महिलाओं के लिए हैं। धार्मिक नेताओं या

सामुदायिक नेताओं को उन जोड़ों को अपनी स्वीकृति देनी चाहिए जो निषिद्ध सम्बंधों की इन श्रेणियों में आते हैं। यदि रजिस्ट्रार यह निर्धारित करते हैं कि सम्बंध सार्वजनिक नैतिकता या रीति-रिवाजों का उल्लंघन करता है तो वे पंजीकरण से इनकार कर सकते हैं। प्राइवैसी कंसर्न (न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ) के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत गोपनीयता के अधिकार का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है, साथ ही लोगों के निजी जीवन पर अधिक आधिकारिक निगरानी भी की जा रही है। नये नियमों से जातियों और धर्मों के बीच सम्बंधों में संभावित बाधाएँ उत्पन्न होने से चिंताएँ उत्पन्न हो गई हैं। आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 125 और पीडब्ल्यूडीवीए, 2005, वर्तमान में लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं को भरण-पोषण का अनुरोध करने की अनुमति देते हैं; हालाँकि, ये अधिकार अयोग्य नहीं हैं। कानूनी विवाह उन लोगों से उत्पन्न हो सकते हैं जो लंबे समय तक ऐसे रिश्तों के प्रति प्रतिबद्ध हुए बिना उनमें प्रवेश करते हैं, लेकिन बाद में अपने कानूनी अधिकारों का दावा करते हैं। विशेषकर रूढ़िवादी समुदायों में, यह सहवास के नैतिक परिणामों तथा विवाह और परिवार के पारंपरिक विचारों पर प्रश्न उठाता है। यद्यपि उत्तराखंड यूसीसी लिव-इन पार्टनरशिप को कानूनी संरक्षण और मान्यता प्रदान करना चाहता है, लेकिन यह गोपनीयता और

सरकारी हस्तक्षेप के महत्वपूर्ण मुद्दे भी उठाता है। नए नियमों को इस तरह लागू करने के लिए कि सामाजिक संरक्षक को बढ़ावा मिले और व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा हो, रिश्तों को नियंत्रित करने और व्यक्तिगत स्वायत्तता को बनाए रखने के बीच संतुलन बनाना आवश्यक होगा। यदि समान नागरिक संहिता व्यक्तिगत कानूनों का स्थान ले ले, तो सहवास में महिलाओं की समानता की गारंटी पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

लिव-इन रिलेशनशिप के मुश्किल से 10% मामलों ही शादी तक पहुँच पाते हैं। बाकी 90% मामलों में रिश्ते टूट ही जाते हैं। ठीक उसी तरह, जिस तरह आजकल के नवयुवक प्रेमी-प्रेमिकाएँ जितनी तेजी से प्रोपोज करते हैं उतनी ही तेजी से ब्रेकअप और फिर उतनी ही तेजी से प्रेमी भी बदल लेते हैं। ऐसे प्रेमी-प्रेमिकाओं को लिव-इन रिलेशनशिप जैसी लुभावनी प्रथा सही लगती है। क्योंकि उन्हें एक दूसरे के साथ बिना शादी के पति-पत्नी जैसा रहने का मौका मिल जाता है और पति-पत्नी जैसे रिश्ते का अर्थ आप अच्छी तरह समझते हैं। इसीलिए रिश्ता टूटने के बाद सबसे ज्यादा जीवन बर्बाद लड़कियों का होता है। विशेषकर विवाह के समान भरण-पोषण और उत्तराधिकार के अधिकार प्रदान करना। सहवास में जन्मे बच्चों की कानूनी स्थिति को स्पष्ट करना, विशेष रूप से वैधता और उत्तराधिकार अधिकारों के सम्बंध में। रिश्ता टूटने के बाद अक्सर लड़कियाँ आत्महत्या जैसे क्रदम उठा लिया करती हैं।

## अल्पावधि पाठ्यक्रमों में उज्वल भविष्य का निर्माण करें

विजय गर्ग

आज के युग में नौकरी पाने के लिए बहुत प्रतिस्पर्धा है। हर विद्यार्थी को यह जरूर सोचना चाहिए कि वह कौन सा कोर्स या पढ़ाई करे जिससे उसे जल्दी अच्छी नौकरी मिल सके। इस उम्र में सबसे बड़ी कठिनाई होती है कोर्स का चयन करना। आइये बात करते हैं 'अल्पकालिक पाठ्यक्रमों' की, जिन्हें अल्पावधि पाठ्यक्रम कहा जाता है। जैसा कि ज्ञात है, लघु-अवधि पाठ्यक्रम बहुत कम समय में पूरे हो जाते हैं। ये पाठ्यक्रम आमतौर पर तीन महीने से एक वर्ष तक चलते हैं। कई विश्वविद्यालय और कॉलेज ये पाठ्यक्रम संचालित करते हैं और कुछ निजी संस्थानों को भी सरकार द्वारा ऐसे पाठ्यक्रम संचालित करने की मंजूरी दी गई है। बिजनेस अकाउंटिंग और टैक्सेशन: कोई भी छात्र 12वीं कक्षा पास करने के बाद यह कोर्स कर सकता है। यह कोर्स मुख्य रूप से कॉमर्स से 12वीं पास करने वाले छात्रों के लिए फायदेमंद है। यह पाठ्यक्रम तीन महीने में पूरा किया जा सकता है। छोटे व्यवसायिक प्रतिष्ठान ऐसे छात्रों को अपने व्यवसाय के लेखा-जोखा के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट या अकाउंटेंट नियुक्त करने का अवसर देते हैं। कार्य में अनुभव प्राप्त करने के बाद वे अपने कार्य के आधार पर बड़े प्रतिष्ठानों में नौकरी भी प्राप्त कर सकते हैं। जावा डेवलपर जावा एक ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड भाषा है, जो हमें विभिन्न कंप्यूटर/मोबाइल एप्लिकेशन बनाने की विशेषज्ञता प्रदान करती है। जावा प्रौद्योगिकी आधारित सॉफ्टवेयर लगभग हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर काम करता है। दुनिया भर में एक लोकप्रिय कंप्यूटर भाषा होने के नाते, 'जावा' नौकरियों में उच्च स्कोर पाने का अवसर प्रदान करती है। जो लोग इस भाषा को जानते हैं उन्हें अच्छे वेतन और नौकरी मिलती है। जावा डेवलपर कोर्स की अवधि तीन से छह महीने तक होती है। इस कोर्स को पूरा करने के बाद निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों में नौकरी के अनेक अवसर मिलते हैं। बिजनेस विश्लेषक बिजनेस विश्लेषक का काम बिजनेस डेटा का विश्लेषण करना है। वे



वस्तुओं और सेवाओं आदि के संबंध में व्यवसायों के लिए प्रासंगिक डेटा प्रदान करते हैं। इस पद पर काम करने के लिए तीन से छह महीने का बिजनेस एनालिसिस कोर्स उपलब्ध है। इस कोर्स को पूरा करने के बाद छात्र व्यावसायिक संगठनों में बिजनेस विश्लेषक के रूप में काम कर सकते हैं। इस क्षेत्र में उन्नति के अनेक अवसर हैं तथा योग्यता के अनुसार आय भी बढ़ती है। मशीन लर्निंग में सर्टिफिकेट कोर्स मशीन लर्निंग पाठ्यक्रम बहुत तेजी से उभर रहे हैं। इस कोर्स को पूरा करने के बाद किसी व्यावसायिक संगठन में नौकरी पाने वाला छात्र डेटा विज्ञान के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता और कौशल के कारण अच्छा पद प्राप्त कर सकता है। इस पाठ्यक्रम की अवधि 6 माह है। कोई भी बारहवीं, स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री वाला छात्र ऐसा कर सकता है।

वित्तीय नियोजक प्रमाणित पाठ्यक्रम यह पाठ्यक्रम उन सभी व्यक्तियों के लिए दुनिया का

सर्वोत्तम प्रमाणित पाठ्यक्रम है जो शिक्षा मूल्यांकन, अभ्यास और नैतिकता के मानकों को पूरा करते हैं। एफपीसीटी इंडिया को वित्तीय योजनाकार के रूप में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सीएफपीसी प्रमाणित से सम्मानित किया गया है। सीएफपीसी प्रमाणित पाठ्यक्रम कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद, बंगलुरु, पुणे और नई दिल्ली में उपलब्ध है। यह पाठ्यक्रम 6 महीने में पूरा होता है। इस कोर्स के बाद नौकरी के अच्छे अवसर भी उपलब्ध हैं। उपरोक्त पाठ्यक्रमों के अलावा कई अन्य पाठ्यक्रम भी हैं जिन्हें विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार 3 से 6 माह की अवधि में पूरा किया जा सकता है। इन पाठ्यक्रमों को पूरा करने के बाद छात्र अपना खुद का व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। इच्छानुसार चुन सकते हैं।

विजय गर्ग सेवानिवृत्त प्रिंसिपल शैक्षिक स्तंभकार मलोट पंजाब

## मस्तिष्क में बढ़ रहे प्लास्टिक के सूक्ष्म कण

### आपके ब्रेन में इतने पर्येंट प्लास्टिक !



विजय गर्ग

इंसानी शरीर में बढ़ते प्लास्टिक के सूक्ष्म कणों को लेकर वैज्ञानिकों ने नया खुलासा किया है। एक नए अध्ययन से पता चला है कि इंसानी दिमाग में प्लास्टिक के इन महीन कणों का स्तर तेजी से बढ़ रहा है। इससे मस्तिष्काघात और ट्यूमर का खतरा बढ़ता जा रहा है।

इंसानी शरीर में बढ़ता प्लास्टिक के सूक्ष्म कणों का स्तर एक बड़े खतरों को उजागर करता है। शोध में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि गुदों और लीवर की तुलना में इंसानी मस्तिष्क में प्लास्टिक के कहीं अधिक महीन कण जमा हो रहे हैं। इस अध्ययन के नतीजे अंतरराष्ट्रीय जर्नल नेचर मेडिसिन में प्रकाशित हुए हैं। इस अध्ययन में वर्ष 1997 से 2024 के बीच किए दर्जनों पोस्टमार्टम में मस्तिष्क के ऊतकों में प्लास्टिक के सूक्ष्म कणों में बढ़ती प्रवृत्ति देखी गई है। इतना ही

नहीं, शोधकर्ताओं को लीवर और गुदों के नमूनों में भी प्लास्टिक के महीन कण मिले हैं। अध्ययन में शोधकर्ताओं ने लीवर, गुदों और मस्तिष्क के नमूनों में प्लास्टिक के सूक्ष्म और नैनोकणों का अध्ययन करने के लिए नए तरीकों की मदद ली है। शोधकर्ताओं ने अपने इस अध्ययन में मस्तिष्क के 52 नमूनों का विश्लेषण किया है। इस दौरान 2016 में 28 नमूनों का, जबकि 2024 में 24 नमूनों का विश्लेषण किया गया। लीवर और किडनी के जो नमूनों लिए गए थे उनमें प्लास्टिक का स्तर करीब-करीब समान था। हालाँकि, मस्तिष्क के नमूने जो फ्रंटल कोर्टेक्स हर्सेसे लिए गए थे उनमें प्लास्टिक का स्तर बेहद अधिक था।

विश्लेषण में यह भी सामने आया है कि 2024 के लीवर और मस्तिष्क के नमूनों में प्लास्टिक के महीन कणों का स्तर 2016 की तुलना में बहुत अधिक था। उन्होंने इन निष्कर्षों की तुलना 1997

से 2013 के बीच लिए मस्तिष्क के ऊतकों के नमूनों से भी की है और पाया है कि हाल के नमूनों में प्लास्टिक के कणों का स्तर कहीं अधिक है।

इसी तरह स्वस्थ लोगों की तुलना में डिमेंशिया से पीड़ित 12 लोगों के मस्तिष्क में प्लास्टिक के सूक्ष्म कणों की कहीं अधिक मौजूदगी का भी पता चला है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि डिमेंशिया से पीड़ित लोगों के मस्तिष्क के नमूनों में प्लास्टिक के सूक्ष्म कणों का स्तर छह गुना अधिक था। शोधकर्ताओं के मुताबिक डिमेंशिया से होने वाले नुकसान से इन कणों की संख्या बढ़ सकती है। हालाँकि वे यह पक्के तौर पर नहीं कह सकते कि यह डिमेंशिया का कारण बनता है। गौरतलब है कि पिछले पांच दशकों में प्लास्टिक एक बड़े खतरों के रूप में उभरा है। यही वजह है कि कंचे पहाड़ों से लेकर गहरे समुद्र तक आज धरती की शायद ही ऐसी कोई जगह है, जहाँ प्लास्टिक की मौजूदगी न हो।

# गौतम अडानी का समूह कितना देता है टैक्स? ये आंकड़े बता रहे हैं इकनॉमी में रोल

परिवहन विशेष न्यूज

अडानी समूह ने वित्त वर्ष 2023-24 में 58,104 करोड़ रुपये का टैक्स चुकाया। यह पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 25% अधिक है। पिछले साल 46,610 करोड़ रुपये का टैक्स जमा किया गया था। अडानी समूह ने अपनी टैक्स ट्रांसपैरेंसी रिपोर्ट भी जारी की है जिससे समूह की पारदर्शिता प्रदर्शित होती है।

नई दिल्ली। अडानी समूह ने वित्त वर्ष 2023-24 में 58,104 करोड़ रुपये का टैक्स चुकाया। यह पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 25% अधिक है। पिछले साल 46,610 करोड़ रुपये का टैक्स जमा किया था। इस जानकारी को रविवार को सार्वजनिक किया गया। इसमें सभी तरह के टैक्स शामिल हैं। जैसे, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर और कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा का योगदान। समूह ने अपनी टैक्स ट्रांसपैरेंसी रिपोर्ट भी जारी की है। यह रिपोर्ट वित्त वर्ष 2023-24 (अप्रैल 2023 से मार्च 2024) के लिए है। समूह का कहना है कि वह भारत के सबसे बड़े करदाताओं में से एक है।

**टैक्स कॉन्ट्रिब्यूशन में बड़ा उछाल**  
अडानी समूह ने बताया कि उसने पिछले वित्त वर्ष की तुलना में ज्यादा टैक्स चुकाया है। वित्त वर्ष 2022-23 में 46,610 करोड़ रुपये टैक्स चुकाया गया था। 2023-24 में यह आंकड़ा बढ़कर 58,104 करोड़ रुपये हो गया है। यह लगभग 25% की बढ़ोतरी है। इसमें सभी तरह



## कितना दिया टैक्स?

के टैक्स शामिल हैं। जैसे, अंतरराष्ट्रीय कर, शुल्क, अडानी पोर्टफोलियो कंपनियों की ओर से चुकाया गया टैक्स, अन्य हितधारकों की ओर से जमा किया गया अप्रत्यक्ष कर और कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा का योगदान। गुपुन यह भी बताया कि वह पूरी पारदर्शिता के साथ काम करता है। इसलिए उसने अपनी कर पारदर्शिता रिपोर्ट भी जारी की है। यह रिपोर्ट वित्त वर्ष 2023-24 के लिए है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि वित्त वर्ष 2023-24 में अडानी समूह का कुल टैक्स कॉन्ट्रिब्यूशन 58,104.4 करोड़ रुपये रहा। यह पिछले वित्त वर्ष 2022-23 के 46,610.2 करोड़ रुपये से काफी ज्यादा है।

सात ल स्टिड कंपनी धिों पर आधारित हैं आंकड़े

यह रिपोर्ट सात सूचीबद्ध कंपनियों की ओर से प्रकाशित स्वतंत्र रिपोर्ट पर आधारित है। ये कंपनियाँ हैं- अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकनॉमिक जोन, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस, अडानी पावर, अडानी टोटल गैस और अंबुजा सीमेंट्स। इसके अलावा, तीन अन्य सूचीबद्ध कंपनियों - एनडीटीवी, एसीसी और सांघी इंडस्ट्रीज - की ओर से चुकाया गया टैक्स भी इस आंकड़े में शामिल है। ये तीनों कंपनियाँ भी अडानी समूह का हिस्सा हैं। अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने इस बारे में अपनी राय भी दी। उन्होंने

कहा, 'भारत के राजकोष में हम खुद को सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक मानते हैं कि हमारी जिम्मेदारी अनुपालन से कहीं बढ़कर है। यह ईमानदारी और जवाबदेही के साथ काम करने के बारे में भी है। हमारे देश के वित्त में हमारा हर एक रुपया पारदर्शिता और सुशासन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।'

उन्होंने आगे कहा, 'इन रिपोर्टों को स्वेच्छा से जनता के साथ साझा करके हमारा उद्देश्य हितधारकों का भरोसा बढ़ाना और जिम्मेदार कॉर्पोरेट आचरण के लिए नए मानक स्थापित करना है।' इससे पता चलता है कि अडानी समूह न केवल अपना टैक्स चुकाने में, बल्कि पारदर्शिता बनाए रखने में भी विश्वास रखता है।

# क्रिप्टो की दुनिया में एक और बड़ी चोरी, हैकर्स ने उड़ाए 13000 करोड़ रुपये के इथेरियम



परिवहन विशेष न्यूज

अगर आप क्रिप्टोकॉर्सी में निवेश करते हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। क्रिप्टोकॉर्सी एक्सचेंज Bybit से करीब 13 हजार करोड़ रुपये की डिजिटल कॉर्सी चोरी हो गई है। यह इतिहास की सबसे बड़ी क्रिप्टो चोरियों में से एक है। इस चोरी को उत्तर कोरिया के लाजरस गुपु से जोड़ा जा रहा है।

नई दिल्ली: क्रिप्टो की दुनिया में एक बहुत बड़ी चोरी हुई है। क्रिप्टोकॉर्सी एक्सचेंज बायबिट (Bybit) से 1.5 अरब डॉलर (करीब 13 हजार करोड़ रुपये) की डिजिटल कॉर्सी गायब हो गई है। यह इतिहास की सबसे बड़ी क्रिप्टो चोरियों में से एक है। इससे पहले भारतीय क्रिप्टोकॉर्सी एक्सचेंज वजीरएक्स से भी दो हजार करोड़ रुपये की चोरी हुई थी।

कंपनी के CEO वेन झोउ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए इस चोरी के बारे में

बताया है। उन्होंने बताया कि एक हैकर ने Bybit के एक ऑफलाइन इथेरियम (Ethereum) वॉलेट पर कब्जा कर लिया। इसके बाद कई ट्रांजेक्शन करके पैसों की चोरी की गई। बिटकॉइन के बाद इथेरियम दुनिया की दूसरी सबसे महंगी क्रिप्टोकॉर्सी है।

वेन झोउ ने यह भी बताया कि Bybit के हॉट वॉलेट, वार्म वॉलेट और बाकी सभी ऑफलाइन वॉलेट सुरक्षित हैं। पैसे निकालने का काम भी सामान्य रूप से चल रहा है। Bybit एक क्रिप्टोकॉर्सी एक्सचेंज है जिसके दुनिया भर में 60 मिलियन (6 करोड़) से ज्यादा यूजर्स हैं।

पाई नेटवर्क, लिब्रा टोकन... लॉन्च होते ही धड़ाम हुई ये क्रिप्टोकॉर्सी, दो दिन में आधी से ज्यादा गिर गई कीमत **दियालिया होने का फैला डर**  
इस चोरी के बाद Bybit के यूजर्स घबरा गए। उन्हें लगा कि कहीं कंपनी दिवालिया तो नहीं हो जाएगी। इसलिए लोगों ने जल्दी-जल्दी अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया। हालांकि,

झोउ ने कहा, 'Bybit दिवालिया नहीं होगा। चाहे यह पैसा वापस मिले या नहीं। कस्टमर का पैसा सुरक्षित है। हम इस नुकसान को भरपाई कर सकते हैं।' **उत्तर कोरिया के हैकर्स पर शक**

CNBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक, Elliptic के विश्लेषकों ने इस हमले को उत्तर कोरिया के लाजरस गुपु से जोड़ा है। यह एक सरकारी हैकिंग गुपु है जो क्रिप्टोकॉर्सी इंडस्ट्री से अरबों डॉलर चुराने के लिए बंदनाम है। **भारतीय एक्सचेंज पर भी हुआ था अटैक**

पिछले साल जुलाई में भारतीय क्रिप्टोकॉर्सी एक्सचेंज WazirX पर सबसे बड़ा साइबर हमला हुआ था। इसमें 235 मिलियन डॉलर (करीब दो हजार करोड़ रुपये) का नुकसान हुआ था। इस हमले का भी पता उत्तर कोरियाई हैकर्स तक लगा था। उस समय WazirX के को-फाउंडर निशचल शेटी ने कहा था, 'हमें यकीन है कि यह (उत्तर कोरिया का) लाजरस गुपु हो सकता है।'

# फरवरी में शेयर बाजार से निकले 23,710 करोड़ रुपये, पिछले महीने के मुकाबले संभली स्थिति

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने इस महीने (21 फरवरी तक) अबतक भारतीय शेयरों से 23,710 करोड़ रुपये निकाले हैं। इससे पहले जनवरी में उन्होंने 78,027 करोड़ रुपये के शेयर बेचे थे।

पिछले काफी समय से शेयर बाजार में लगातार गिरावट का दौर जारी है। विशेषज्ञों का मानना है कि, बाजार में लगातार हो रही गिरावट के पीछे की वजह विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा लगातार की जा रही है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने इस महीने अबतक भारतीय शेयर बाजार से 23,710 करोड़ रुपये से अधिक की निकासी की है। इस तरह 2025 में अबतक एफपीआई भारतीय शेयरों से एक लाख करोड़ रुपये से अधिक निकाल चुके हैं।

**पिछले महीने के मुकाबले इस महीने संभली स्थिति**

डिपॉजिटरी के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने इस महीने (21 फरवरी तक) भारतीय शेयरों से 23,710 करोड़ रुपये निकाले हैं। जबकि पिछले जनवरी में उन्होंने 78,027 करोड़ रुपये के शेयर बेचे थे। साल 2025 में अबतक एफपीआई 1,01,737 करोड़ रुपये की बिकवाली कर चुके हैं। इतनी जबरदस्त बिकवाली के चलते निफ्टी ने भी चार प्रतिशत का नकारात्मक रिकॉर्ड दिया है।

**बॉन्ड बाजार से भी निकासी**  
समीक्षाधीन अवधि में एफपीआई ने त्रया या बॉन्ड बाजार से भी निकासी हुई है। उन्होंने बॉन्ड में सामान्य सीमा के तहत 7,352 करोड़ रुपये और स्विच्छक

प्रतिधारण मार्ग से 3,822 करोड़ रुपये निकाले हैं। कुल मिलाकर विदेशी निवेशकों सतर्क रुख अपना रहे हैं। एफपीआई का 2024 में भारतीय बाजार में निवेश काफी कम होकर 427 करोड़ रुपये रहा था। इससे पहले 2023 में उन्होंने भारतीय बाजार में 1.71 लाख करोड़ रुपये डाले थे, जबकि 2022 में वैश्विक केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज दरों में आक्रामक वृद्धि के बीच 1.21 लाख करोड़ रुपये की निकासी की थी।

**ट्रंप की नीतियों ने डाला असर**  
मॉनिंगस्टार इन्वेस्टमेंट रिसर्च इंडिया के एसोसिएट निदेशक-प्रबंधक हिमांशु श्रीवास्तव ने कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कई देशों पर जवाबी शुल्क के साथ-साथ इस्पात और एल्यूमीनियम के आयात पर नए शुल्क लगाने पर विचार करने की रिपोर्ट के बाद बाजार की चिंताएं बढ़ गई हैं। उन्होंने कहा कि इन घटनाक्रमों ने संभावित वैश्विक व्यापार युद्ध की आशंकाओं को फिर से जगा दिया है, जिसने एफपीआई को भारत सहित उभरते बाजारों में अपने जोखिम का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित किया है।

**बाजार का रुख- 'भारत में बेचो और चीन में खरीदो रुख'**

जियोजीत फाहनीशियल सर्विसेज के विजयकुमार ने कहा कि ट्रंप की राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद अमेरिका बाजार में शेष दुनिया से भारी पूंजी का प्रवाह हो रहा है। उन्होंने कहा, 'चूँकि चीन के शेयर सस्ते हैं ऐसे में 'भारत में बेचो और चीन में खरीदो' का रुख अभी जारी रह सकता है। विजयकुमार का मानना है कि भारत में एफपीआई निवेश का पुनरुद्धार तब होगा जब आर्थिक वृद्धि और कंपनियों की आय में सुधार होगा।

# पीएम मोदी जारी करेंगे 19वीं किस्त, 10 करोड़ किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर होंगे 22000 करोड़ रुपये

परिवहन विशेष न्यूज

पीएम किसान योजना की किस्त का किसानों का इंतजार खत्म होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार में होंगे। वह वहीं से इस योजना की 19वीं किस्त किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। इस योजना से किसानों को आर्थिक मदद मिलती है।

नई दिल्ली: 24 फरवरी को किसानों के बैंक अकाउंट में पैसे आने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त जारी करेंगे। इस दौरान देश के करीब 10 करोड़ किसानों को 22 हजार करोड़ रुपये की रकम ट्रांसफर की जाएगी। इनमें 2.41 करोड़ महिला किसान भी शामिल हैं। यह पैसा सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में जाएगा।

पीएम मोदी कल बिहार के दौर पर होंगे। वह बिहार के भागलपुर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी करेंगे। इस योजना से किसानों को आर्थिक मदद मिलती है। यह योजना किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस योजना के तहत हर किसान के अकाउंट में दो हजार रुपये की रकम आती है।

कितनी संपत्ति की मालकिन हैं दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी? अब विधानसभा में होंगी विपक्ष की नेता, जानें कितना है कैश **क्या है पीएम किसान योजना?**  
इस योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना 6000 रुपये मिलते हैं। हर चार महीने में 2000



## कब आएगी किसानों के खाते में रकम?

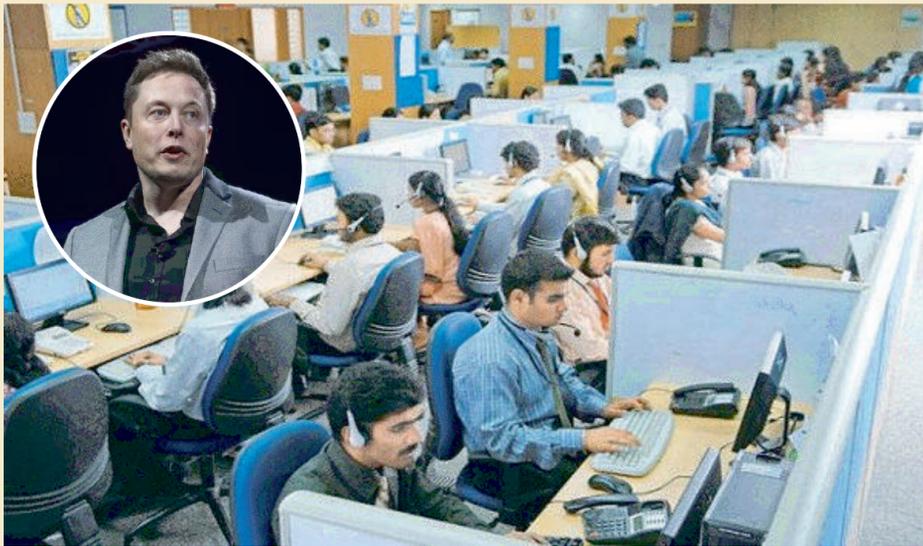
रुपये की किस्त उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है। पहले इस योजना का लाभ 9.60 करोड़ किसानों को मिलता था। अब लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 9.80 करोड़ हो गई है। 19वीं किस्त के साथ ही अब तक किसानों को कुल 3.68 लाख करोड़ रुपये मिल चुके होंगे। इस योजना की शुरुआत साल 2019 में हुई थी।

किस मिलता है इस स्कीम का फायदा?

पीएम किसान सम्मान योजना का लाभ हर किसान को नहीं मिलता। इसके लिए कई शर्तों का पूरा करना जरूरी है। सबसे बड़ी शर्त सरकारी नौकरी का नहीं होना है। यानी किसान सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। साथ ही किसान कोई इनकम टैक्स न भरता हो। किसान के परिवार में अगर एक से ज्यादा लोग हैं तो इसका लाभ सिर्फ एक ही सदस्य को मिलेगा।

**किसानों को कई तरह से मिलती है मदद**  
इस रकम का इस्तेमाल किसान अपने कई तरह के खर्च में कर सकते हैं। इससे किसानों को अपनी खेती से संबंधित उपकरण खरीदने में काफी मदद मिलती है। साथ ही वे उन्नत किस्म के बीज खरीद सकते हैं। इस रकम से किसान उर्वरक आदि भी खरीद सकते हैं। बता दें कि किसान सम्मान योजना दुनिया की सबसे बड़ी बीबीटी स्कीम है।

# काम का हिसाब 48 घंटे में दीजिए, नहीं तो नौकरी से छुट्टी... मस्क ने सरकारी कर्मचारियों को दी चेतावनी



अमेरिका में सरकारी कर्मचारियों की नौकरी खतरे में पड़ गई है। एलन मस्क ने लाखों कर्मचारियों को ईमेल भेजकर उनसे काम का हिसाब मांगा है। मस्क ने इसके लिए कर्मचारियों को 48 घंटे का समय दिया है। जो काम का हिसाब नहीं देगा, उसकी नौकरी से छुट्टी की जाएगी।

नई दिल्ली: अमेरिकी कारोबारी और DOGE डिपार्टमेंट प्रमुख एलन मस्क ने सरकारी कर्मचारियों को चेतावनी दी है। उन्होंने कर्मचारियों से उनके काम का हिसाब-किताब मांगा है। इसके लिए उन्होंने दो दिन का समय दिया है। इस दौरान उन्हें बताया होगा कि उन्होंने पिछले हफ्ते क्या काम किया। हिसाब न देने वाले की नौकरी से छुट्टी कर दी जाएगी। DOGE का काम सरकारी खर्च में कटौती करना है। मस्क के आदेश के बाद लाखों संघीय

कर्मचारियों के पास सिर्फ 48 घंटे हैं। उन्हें बताया है कि पिछले हफ्ते उन्होंने क्या काम किया। ये सब मस्क की उस मुहिम का हिस्सा है जिसमें वो सरकारी खर्च में कटौती करना चाहते हैं। मस्क इसे 'हर जगह बर्बादी' बताते हैं। मस्क ने हिसाब-किताब की जानकारी देने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट की थी।

**क्या लिखा है मस्क ने पोस्ट में?**  
मस्क ने अपनी पोस्ट में लिखा है, 'राष्ट्रपति ट्रंप के निर्देशों के अनुसार सभी संघीय कर्मचारियों को जल्द ही एक ईमेल मिलेगा। इसमें उनसे पूछा जाएगा कि उन्होंने पिछले हफ्ते क्या काम किया।' उन्होंने आगे लिखा, 'जवाब ना देने को इस्तीफा माना जाएगा।'  
इसके कुछ देर बाद ही कर्मचारियों को तीन लाइन का एक ईमेल मिला। इसमें लिखा था, 'कृपया इस ईमेल का जवाब देते हुए लगभग 5

बिंदुओं में बताएं कि आपने पिछले हफ्ते क्या काम किया। अपने मैनेजर को भी CC करें।' जवाब देने की आखिरी तारीख सोमवार रात 11:59 बजे है।

**काफी कर्मचारियों को निकाला जा चुका है**

ट्रंप प्रशासन के पहले महीने में ही हजारों सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है। कुछ को बर्खास्त कर दिया गया है तो कुछ को रिटायरमेंट का प्रस्ताव दिया गया। 'द्वैड हाउस और मस्क का डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी (DOGE) नए और पुराने, दोनों तरह के कर्मचारियों को निकाल रहा है। एजेंसी के प्रमुखों को बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की छंटनी की योजना बनाने और अरबों डॉलर के संघीय अनुदान को रोकने के लिए कहा गया है।

# स्टारलिनक सैटेलाइट इंटरनेट मुहैया कराएं; अमेरिकी अरबपति से बांग्लादेशी सरकार की अपील



परिवहन विशेष न्यूज

**बांग्लादेश की सरकार ने बेहतर इंटरनेट सेवाओं के लिए अमेरिकी अरबपति एलन मस्क को पत्र लिखा है। स्टारलिनक सैटेलाइट इंटरनेट मुहैया कराने की अपील करते हुए अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस ने पत्र लिखा है।**

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस ने अरबपति अमेरिकी कारोबारी एलन मस्क को बांग्लादेश आने का निमंत्रण दिया है। उन्होंने देश में स्टारलिनक सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए अमेरिका के शीर्ष व्यवसायी और स्पेसएक्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मस्क को पत्र लिखा। 19 फरवरी को लिखे पत्र में यूनुस ने मस्क से कहा, उनकी बांग्लादेश यात्रा से उन्हें युवा बांग्लादेशी पुरुषों और महिलाओं से मिलने का मौका मिलेगा, जो इस अग्रणी तकनीक के मुख्य लाभार्थियों में से होंगे।

**स्टारलिनक की कनेक्टिविटी से परिवर्तनकारी असर**

उन्होंने बेहतर भविष्य के लिए अपने आपसी दृष्टिकोण को साकार करने के लिए मस्क से मिलकर काम करने का आह्वान किया। सरकारी समाचार एजेंसी बीएसएस ने रविवार को बताया, बांग्लादेश के बुनियादी ढांचे में स्टारलिनक की कनेक्टिविटी से परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ेगा। इससे बांग्लादेश के उद्यमी युवाओं, ग्रामीण और कमजोर महिलाओं और दूरदराज और वंचित समुदायों को विशेष लाभ मिलेगा।

# भारत ने पाकिस्तान से लिया 2017 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में हार का बदला

भारत ने पाकिस्तान को दिखाया बाहर का रास्ता

पाकिस्तान		भारत	
सक्रिय शकील	62 रन	241	244/4
कुलदीप यादव	3 विकेट	(49.4 ओवर)	(42.3 ओवर)
विराट कोहली	100* रन		
शाहीन अफरीदी	2 विकेट		

भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी में अब दो मैच जीत लिए हैं और सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। वहीं, पाकिस्तान की टीम लगभग चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गई है। उसे अब अन्य टीमों के नतीजों पर निर्भर रहना होगा।

नई दिल्ली। भारत ने पाकिस्तान को छह विकेट से हरा दिया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की टीम 49.4 ओवर में 241 रन पर सिमट गई थी। जबकि भारत ने 42.3 ओवर में चार विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। विराट कोहली ने वनडे करियर का 51वां शतक लगाया। वह 111 गैट 100 रन बनाकर नाबाद रहे। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान विराट को शतक नहीं बनाने देने की साजिश रच रहा है। शाहीन वाइड पर वाइड फेंक रहे थे। 43वें ओवर में भारत को जीत के लिए चार रन और कोहली को शतक के लिए पांच रन चाहिए थे। 43वें ओवर की पहली गेंद पर कोहली ने एक रन लिया। फिर अगली गेंद पर अक्षर ने एक रन लिया। तीसरी गेंद पर विराट ने चौका लगाकर शतक भी पूरा किया और भारत को जीत भी दिलाई।

भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी में अब दो मैच जीत लिए हैं और सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। वहीं, पाकिस्तान की टीम लगभग चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गई है। उसे अब अन्य टीमों के नतीजों पर निर्भर रहना होगा। भारत के दो मैचों के बाद चार अंक हैं, जबकि पाकिस्तान दो मैचों में खाली नहीं खोल सका है।

## भारत की पारी

242 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी। रोहित आक्रामक खेलने की कोशिश में शाहीन अफरीदी की गेंद पर क्लीन बोल्ट हो गए। वह 15 गेंद पर तीन चौके और एक छक्के की मदद से 20 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद शुभमन गिल और विराट कोहली ने पारी संभाली। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 69 रन की साझेदारी निभाई। गिल अर्धशतक से चूक गए। वह 52 गेंद में सात चौके की मदद से 46 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें अंबरार अहमद ने क्लीन बोल्ट किया। इसके बाद कोहली के साथ भारत को जीत तक ले जाने की जिम्मेदारी श्रेयस अय्यर ने संभाली। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 114 रन की साझेदारी निभाई। खुशदिल शाह ने श्रेयस अय्यर को

इमाम के हाथों कैच कराया। वह 67 गेंद पर पांच चौके और एक छक्के की मदद से 56 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद कोहली ने अक्षर के साथ मिलकर टीम इंडिया को जीत दिलाई।



एक विकेट मिला।

## पाकिस्तान की पारी

इससे पहले पाकिस्तान की टीम 49.4 ओवर में 241 रन पर ऑलआउट हो गई थी। भारत ने वनडे में लगातार पांचवें मैच में विपक्षी टीम को 50 ओवर के अंदर ऑलआउट किया है। भारत की ओर से कुलदीप ने सबसे ज्यादा तीन और हार्दिक पांड्या ने दो विकेट झटकें। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान को बाबर आजम और इमाम उल हक ने संधी हुई शुरुआत दिलाई। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 41 रन की साझेदारी हुई। इस साझेदारी को हार्दिक पांड्या ने तोड़ा। उन्होंने बाबर को विकेटकीपर राहुल के हाथों कैच कराया। वह 26 गेंद पर पांच चौके की मदद से 23 रन बना सके। इसके अगले ही ओवर में इमाम उल हक भी रन आउट हो गए। वह 26 गेंद में 10 रन बना सके। 47 रन पर दो विकेट गिर जाने के बाद सक्रम शकील और कप्तान मोहम्मद रिजवान ने पारी संभाली।

दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 104 रन की साझेदारी हुई। इस बीच शकील ने वनडे करियर का चौथा अर्धशतक लगाया। इस साझेदारी को अक्षर पटेल ने तोड़ा। उन्होंने रिजवान को क्लीन बोल्ट किया। वह 77 गेंद में तीन चौके की मदद से 46 रन बनाकर आउट हुए। उनके आउट होते ही फिर से विकेट की झड़ी लग गई। शकील भी 76 गेंद में पांच चौके की मदद से 62 रन बनाकर हार्दिक पांड्या का शिकार बने। तैयब ताहिर चार रन और सलमान अली आगा 19 रन बनाकर आउट हुए। सलमान को कुलदीप और तैयब को जडेजा ने पवेलियन भेजा। शाहीन अफरीदी खाली नहीं खोल सके। नसीम शाह 14 रन और हारिस रऊफ आठ रन बनाकर आउट हुए। हर्षित राणा ने खुशदिल शाह को कोहली के हाथों कैच कराया और पाकिस्तान की पारी समेट दी। खुशदिल ने 39 गेंद में दो छक्के की मदद से 38 रन की पारी खेली। कुलदीप और हार्दिक के अलावा हर्षित राणा, अक्षर और जडेजा को एक-

## बालेशोर सोरो में रेलगाड़ी पटरी से उतर गई। तभी ट्रेन एक बिजली के खंभे से टकरा गई

मनोरंजन सासमल, स्टेट हेड ओड़िशा



भुवनेश्वर : फिर बालासोर में रेल दुर्घटना। ट्रेन सोरो थाना सबिरे रेलवे स्टेशन से थोड़ी ही दूरी पर बेलसाबिरा के पास पटरी से उतर गई। जब नए ट्रैक पर काम चल रहा था, तभी ट्रेन पटरी से उतर गई और किनारे पर लगे बिजली के खंभे से टकरा गई। हालांकि, अभी तक इस घटना में किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं मिली है। इसी तरह कुछ दिन पहले एक और बड़ी रेल दुर्घटना हुई थी। प्रयागराज से कानपुर जा रही कोयला लदी ट्रेन एक अन्य मालगाड़ी से टकरा गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार, जब मालगाड़ी लाल सिग्नल पर खड़ी थी, तभी पीछे से एक अन्य ट्रेन आई और उससे टकरा गई। हालांकि, दुर्घटना के समय मालगाड़ी के गार्ड सोनू बर्मा ने गाड़ी में कूदकर अपनी जान बचा ली, लेकिन वह घायल हो गया।

## विश्व हिंदू परिषद की दो दिवसीय कार्यकारी समिति की बैठक का उद्घाटन

मनोरंजन सासमल, स्टेट हेड ओड़िशा

भुवनेश्वर : विश्व हिंदू परिषद की दो दिवसीय (22-23/फरवरी/2025) कार्यकारी समिति की बैठक का उद्घाटन आज सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, स्थानीय इकाई-3, भुवनेश्वर में हुआ। बैठक का उद्घाटन पूज्य स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती, भारतीय हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री माननीय डॉ. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बसंत कुमार रथ थे, जबकि कार्यक्रम का उद्घाटन बीएचपी ओड़िशा (पूर्व) राज्य अध्यक्ष प्रफुल्ल मिश्रा, कार्यकारी अध्यक्ष माननीय पृथ्वी कुमार स्वैन, बीएचपी ओड़िशा (पूर्व) राज्य सचिव माननीय पंडित महेश साहू ने मुख्य दीप प्रज्वलित कर किया।

आज के कार्यक्रम में मुख्य वक्ता भारतीय जनता पार्टी ओड़िशा (पूर्व) के राज्य सचिव माननीय पंडित महेश साहू थे। उनके भाषण में सामाजिक समरसता, धर्मांतरण से मुक्त समाज, सुधरे हुए युवा समाज का निर्माण, जन्मनियंत्रण की समस्या, वर्तमान



समय में लिव-इन रिलेशनशिप के कारण समाज में होने वाली समस्याएं, हिंदू युवाओं के विवाह में देरी और हिंदू समाज की अन्य समस्याओं के साथ-साथ वर्तमान समस्याओं पर व्यापक चर्चा हुई। आज की बैठक में भाकियू उपाध्यक्ष शिशिर कुमार साहू, दुर्गा वाहिनी संयोजिका शिप्रा राउत, सह संयोजिका तुकुनी बारिक, मातृशक्ति क्षेत्र संयोजिका शशाही जेना, मातृशक्ति सह संयोजिका प्रणति साहू, सह संपादक उमाशंकर आचार्य, अरुण कुमार पाद्री, शांतनु कुमार स्वामी, कोषाध्यक्ष माननीय संजय कुमार अग्रवाल, बजरंग दल क्षेत्रीय सह-संयोजक पर्वत भूषण त्रिपाठी और शिव नेत्र खडंगा के साथ भाकियू ओड़िशा (पूर्व) संगठन मंत्री माननीय सरत कुमार प्रधान, प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित थे।

## कुर्सी का काला खेल, संगीत का उजला मेल [सत्ता की बिसात पर साजिश, सुरों की धारा में सुकून]

जिदगी मानो दो परस्पर विरोधी धाराओं का अखाड़ा है—एक ओर वह जो सत्ता की पिपासा में अपने कंठ को फाड़कर चीखता है, दूसरी ओर वह जो अपने सुरों की मल्लार से रूह को अमृतपान कराता है। राजनीति वह दलदल है, जहाँ साजिशों की बेलें विषवृक्ष बनकर लहराती हैं, गठबंधनों का सीदा होता है, और अवसर मिलते ही विश्वसनीयता को तिलांजलि दे दी जाती है। इसके ठीक विपरीत, संगीत एक ऐसी निष्पत्ति है, जो लोभ-मोह की मर्यादाओं से परे, बिना किसी छल-प्रपंच के हृदयों को सुरों की अटूट डोर में बाँध देती है। न विश्वासघात, न छलावा—बस एक ऐसी रागिनी जो आत्मा को मधुर आलिंगन में भर लेती है। किंतु विधि का यह कटु सत्य है कि सत्ता का भूत जब किसी पर सवार होता है कि भाई-भाई की पीठ में छुरा घोंप देता है, जबकि सुरों का सच्चा साधक अपने शिष्य को स्वर-सिंधु में डुबोकर उसे अनंत ऊँचाइयों तक पहुँचा देता है।

राजनीति का असली मजा तो उसकी बेशर्मी में छुपा है। कल जो एक दरबार में चरणों में लोट रहे थे, आज दूसरे की चप्पलें चूमते नजर आते हैं। कोई "बड़ा भाई" बनकर पीठ में खंजर मारता है, तो कोई मुलायम की चौखट छोड़कर मोदी के डेरे में तुमक लगाता है। यहाँ न गुरु-शिष्य की मर्यादा, न कोई पवित्र रिश्ता—बस सौदेबाजी की सुई टनटनाती रहती है। मगर संगीत की दुनिया में ऐसा कहीं? वहाँ उस्ताद चढ़ाने-सा अडिग खड़ा रहता है, और शागिद उसकी छाँव में पनपता-चमकता है। उस्ताद को कोई डोंगी बाबा नहीं, जो गले में तांबीज टाँगे घूमने, वह तो सुरों का जादूगर है, जो ऐसी माला गुँथता है कि सीधे ऊपरवाले के दरबार में पहुँच जाए।

राजनीति का ढोल ऐसा बेसुरा कि मजहब के नाम पर चिंगारियाँ भड़काए, और उसकी राख से अपनी गंदी दुकान चलाए। किसी शानदार निशानी को अपने हिसाब से रंग दो, किसी बुलंद छाया को जमीन में मिलाने की साजिश रचो—ये सब इनके घटिया तमाशे हैं, बस भीड़ को ठगने का धंधा। मगर जरा संगीत



की तरफ आँख उठाकर दिखाओ! किसी उस्ताद की शहनाई को मजहब की तलवार से चीरो, किसी सितार की झंकार को हिंदू-मुसलमान की कसौटी पर कसो—है हिम्मत तो करो! तानसेन की रागिनियों में आग की लपटें सुलगाओ, रसखान की बाँसुरी छीनकर उसकी धुन को कुचल दो—सुरों का जोर नहीं टूटेगा, तुम्हारी गर्दन को अकड़ जरूर धूल चाटेगी। आत्मा को अमर का खिताब दो, फिर रूह को जूती तले रोदने की गुस्ताखी करो—किसी रानी के जन्मे गंदे लफ्जों से तोलो, मगर मियाँ की तोड़ी की लय को तोड़ने का दुस्साहस करके दिखाओ! ये कुर्सी के दीवाने हरियाली को अपने झंडे

गायक की गहराई से रूह को थामे—दोनों मिलकर दिल को लट्टू कर देते हैं। चाहे कोई पंडित तान छेड़े, चाहे कोई खान धुन उड़ाए—सुरों की दुनिया में ऊँच-नीच का झमला कहीं? सितार की तारें हों या तबले की थाप—जब साथ में गुँजते हैं, तो मूँह से बस "वाह-वाह" ही फूटता है। "रैना बीती जाए"—ये मियाँ की तोड़ी का ऐसा जादू है, जिसे कुर्सी का कोई पहलवान अपनी भँस की ताकत से भी नहीं मिटा सकता।

सुबह की ताज़गी हो मियाँ की तोड़ी, या बारिश की बूँदों में मेघ मल्लार—ये जिंदगी के सुर हैं, जो राग-रंग में बसते हैं। शिवरंजनी की चुललुकी शारारत हो या ममन की रूहानी सैर—हर साज में एक ही रंग समाता है। मालकौस की धुन बजे, तो मन हरि के पीछे नाचने को बेकरार हो जाए। चाहे सरोद की गहरी आवाज हो, चाहे शहनाई की सीधी आत्मा तक की पुकार—सब एक ही राग में डूबते हैं, और वो है देस का राग। ये राग न कुर्सी की चापलूसी का गुलाम है, न चोटों की ठेकेदारी का भिखारी। ये तो बस यँ ही बहता है, जैसे बादल बिना किसी रोक-टोक के बरसते हैं।

अब जरा राजनीति के ढोल को देखो—शोर मचाए, चिल्ल-पों करे, मगर सुर की एक लकीर भी न पकड़ सके। कुर्सी के नीचे से जमीन खिसक जाए, तो ये सारे बादशाह मुँह के बल धड़ाम से गिर पड़ते हैं। मगर संगीत? वो तो जमीन पर कदम जमाकर आसमान को भी सलाम ठोकने पर मजबूर कर देता है। एक तरफ कुर्सी का तमाशा, जहाँ मजहब के नाम पर तलवारें लहराई जाती हैं, दूसरी तरफ सुरों का जहान, जहाँ दिलों के किवाड़ खुलते हैं। अब फैसला तुम्हारे हाथ—कुर्सी की कर्कश चीखों में कान फोड़ो, या सुरों के सुकून में गोते लगाओ? क्योंकि जहाँ राजनीति की चिल्लाहट थम जाती है, वहीं संगीत का आलाप गुँज उठता है—और वो कभी थमने का नाम नहीं लेता।

प्रो. आरके जैन "अरिजीत", बड़वानी (मग)

## साइबरशाला: सूरजकुंड मेले 2025 में साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान

सूरजकुंड मेला 2025 में इस बार विशेष रूप से साइबर जागरूकता अभियान आयोजित किया गया, जिसमें साइबर ताऊ की पहल से लोगों को साइबर सुरक्षा की बुनियादी जानकारी सरल और प्रभावी तरीके से दी गई। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य आम जनता को साइबर अपराधों से बचाने के लिए जागरूक करना और उन्हें डिजिटल सुरक्षा से जुड़ी आवश्यक जानकारियाँ प्रदान करना था।

साइबर ताऊ, जो कि साइबर सुरक्षा जागरूकता के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित नाम बन चुका है, ने इस अभियान के तहत मेले में आने वाले लोगों को साइबर खतरों, ऑनलाइन धोखाधड़ी, फिशिंग, पर्सनल डेटा सुरक्षा और अन्य डिजिटल सुरक्षा उपायों के बारे में बताया। विशेष रूप से सोशल मीडिया पर सुरक्षित रहने और डिजिटल लेन-देन को सुरक्षित करने के लिए सरल सुझाव दिए गए।

साइबर दोस्त: प्रशासन की नई पहल इस बार की सबसे खास बात यह रही कि प्रशासन विभाग ने 'साइबर दोस्त' नामक एक नई पहल की

